● वर्ष : 17 ● अंक : 209 ● मूल्य : 02 रुपया मात्रा ● पृष्ठ : 08

LKS

RNI NO.: DELHIN / 2008 / 23928
www.loktantrakishaan.com

दैनिक लोकतंत्र की शान

दिल्ली से प्रकाशित बुधवार 20 मई 2026 लोकतंत्र का स्तंभ

राजनाथ सिंह ने वियतनाम यात्रा के पहले दिन द्विपक्षीय वार्ता में रक्षा साझेदारी पर जोर दिया

एजेंसी। नई दिल्ली

दो एशियाई देशों के दौरे पर निकले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यात्रा के पहले दिन वियतनाम के उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग से हनोई में द्विपक्षीय वार्ता की। उन्होंने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता, सुरक्षा, संरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों मंत्रियों ने वियतनाम के एयर फोर्स ऑफिसर्स कॉलेज में 'भाषा प्रयोगशाला' का वर्चुअल उद्घाटन किया। भारत और वियतनाम ने एआई और क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक समझौता किया। रक्षा मंत्री ने न्हा ट्रांग स्थित टेलीकम्युनिकेशंस यूनिवर्सिटी में एक एआई प्रयोगशाला स्थापित करने का ऐलान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 18 से 19 मई तक वियतनाम के दौरे पर हैं, जिसके बाद 19 से 21 मई तक दक्षिण कोरिया की यात्रा करेंगे। उन्होंने मंगलवार को हनोई में वियतनाम के उप प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों मंत्रियों ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रक्षा साझेदारी की समीक्षा की और समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण तथा क्षेत्रीय स्थिरता के क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा घटनाक्रमों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। उन्होंने सैन्य प्रशिक्षण, रक्षा उद्योग सहयोग, समुद्री सुरक्षा, क्षमता निर्माण, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना, साइबर सुरक्षा और उच्च-स्तरीय आदान-प्रदान सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। इसके अलावा नियमित संवाद, संयुक्त अभ्यास और आदान-प्रदान कार्यक्रमों के माध्यम से दोनों देशों के रक्षा बलों के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की। दोनों मंत्रियों ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता, सुरक्षा, संरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। रक्षा मंत्री ने वियतनाम के साथ भारत की 'विस्तारित व्यापक रणनीतिक साझेदारी' को और मजबूत करने, वियतनाम के रक्षा आधुनिकीकरण और क्षमता संवर्धन पहलों में सहयोग देने के भारत के संकल्प को भी दोहराया। जनरल फान वान जियांग ने भारत के निरंतर समर्थन की सराहना की और दोनों देशों के बीच की पुरानी दोस्ती तथा बढ़ती रणनीतिक साझेदारी पर जोर दिया। दोनों रक्षा मंत्रियों ने वर्चुअल माध्यम से वियतनाम के एयर फोर्स ऑफिसर्स कॉलेज में 'लैंग्वेज लैब' का उद्घाटन किया। इस लैब की स्थापना भारत की सहायता से की गई है। रक्षा मंत्री ने न्हा ट्रांग स्थित टेलीकम्युनिकेशंस यूनिवर्सिटी में 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब' स्थापित करने की भी घोषणा की।

वियतनाम के एयर फोर्स ऑफिसर्स कॉलेज में 'भाषा प्रयोगशाला' का वर्चुअल उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री मोदी ने आइसलैंड की प्रधानमंत्री से की मुलाकात

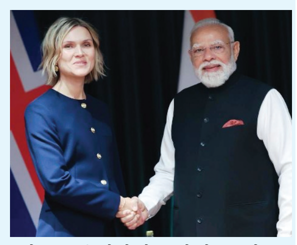

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को नार्वे की राजधानी ओस्लो में नॉर्डिक देशों के साथ आयोजित तीसरे इंडिया-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन से इतर आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्ट्रून फ्रॉस्टाडॉटिर से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के अनुसार बैठक में भू-तापीय और नवीकरणीय ऊर्जा, मत्स्य पालन, व्यापार एवं निवेश, नवाचार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, रचनात्मक अर्थव्यवस्था, आर्कटिक सहयोग तथा लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे विषयों पर विशेष रूप से विचार-विमर्श किया गया। दोनों पक्षों ने भारत-ईएफटीए व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौते (टीईपीए) के क्रियान्वयन से उत्पन्न होने वाले अवसरों पर भी चर्चा की। इसके अलावा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी दोनों नेताओं ने अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर मुलाकात को शानदार बताते हुए कहा कि भारत आइसलैंड के साथ अपनी मित्रता को अत्यधिक महत्व देता है। दोनों देशों ने स्वच्छ ऊर्जा, मत्स्य पालन, सतत विकास, भू-तापीय ऊर्जा, कार्बन कैप्चर एवं स्टोरेज समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। ब्लू इकोनॉमी से जुड़े क्षेत्रों में आइसलैंड की विशेषज्ञता सराहनीय है। हमें उम्मीद है कि ऐतिहासिक भारत-ईएफटीए टीईपीए समझौते से व्यापार और निवेश संबंधों को भी नई गति प्रदान करेगा।

ज्वलंत मुद्दा | संपादकीय

लोकतंत्र में नागरिक कॉकरोच, न्यायपालिका ने पहचाना?

देश में पिछले कुछ वर्षों में आंदोलनों, विरोध प्रदर्शनों और असहमति की आवाज़ों को शासन और प्रशासन द्वारा कठोरता के साथ दबाया जा रहा है। आंदोलनकारियों और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के लाठी डंडे, अश्रु गैस के बाद अब कठोर कानूनी धाराओं का उपयोग शुरू कर दिया गया है। पिछले कुछ वर्षों में एनएसए जैसी राष्ट्र विरोधी कार्यों वाली धाराओं का उपयोग प्रदर्शनकारियों, पत्रकारों, छात्रों, किसानों पर हो रहा है। लोकतंत्र की सेहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव अधिकारों का कारण बनती है। इस पर गंभीर बहस खड़ी हो गई है। छात्र, मजदूर, किसान, पत्रकार, राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता कोई भी जांच एजेंसियों के दमन और कठोर कानूनों की कार्रवाई से अछूता नहीं रहा।

सरकारें चाहे केंद्र की हों या राज्यों की, सरकार के विरोध को "कानून-व्यवस्था" के स्थान पर अब राष्ट्र का विरोध मान लिया गया है। सरकार के निर्देश पर लंबे समय तक जेल में रखने की नीति जाँच एजेंसियाँ अपना रही हैं। इससे समाज के सभी वर्गों में असंतोष और सरकारों के प्रति गुस्सा बढ़ रहा है। अब यह गुस्सा और अविश्वास कहीं ना कहीं न्यायपालिका पर भी दिखने लगा है। अदालतें सरकार के दबाव में जमानत जैसे मामलों में कई महीने और सालों तक लटकाकर रख रही हैं। सारी विधि व्यवस्था को न्यायपालिका स्वयं नजर अंदाज कर रही है। ऐसी स्थिति में अब न्यायपालिका के ऊपर आम नागरिकों को वह विश्वास नहीं रहा, जो पहले होता था। लोकतंत्र केवल चुनावों से नहीं चलता है। नागरिकों को अपनी बात कहने, सरकार से सवाल पूछने और शांतिपूर्ण विरोध करने के अधिकार से लोकतंत्र मजबूत होता है। सरकारें नागरिकों के प्रति जवाबदेह होती हैं।

संविधान ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिकों के विरोध के अधिकार को मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी है। पिछले कुछ वर्षों से आंदोलनकारियों पर गंभीर धाराएं लगाकर साजिशन महीनों या वर्षों तक जेल में रखा जा रहा है। बाद में पर्याप्त सबूत न मिलने पर वर्षों बाद आरोपी अदालत से बरी हो जाते हैं। तब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कानून का उपयोग न्याय के लिए हो रहा है? सरकार से असहमति, आंदोलन, प्रदर्शन और विरोध को नियंत्रित करने के लिए कानूनों का दुरूपयोग किया जा रहा है। हाल के वर्षों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं। लंबी हिरासत के बाद अदालतों में आरोपियों पर जो आरोप लगे थे, उससे संबंधित कोई तथ्य ही मुकदमे में नहीं था। अदालत में जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठे। उसके बाद भी इन मामलों में कोई रोक नहीं लगी। ईडी, सीबीआई, पुलिस इत्यादि जांच एजेंसियां गंभीर धाराओं में आरोपियों को बंद करके जाँच एवं पूछताछ के नाम पर कई महीनो तक जेल में बंद रखती हैं।

सैयद जकी हैदर | सम्पदक/प्रकाशक
MOBE NO.9911371802
EMAIL. SYEDZAKIHAIDER786@GMAIL.COM

संक्षिप्त समाचार

जम्मू-कटरा रेलखंड पर ढलान को स्थिर करने और सुरंगों की मरम्मत को 238 करोड़ की मंजूरी

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने उत्तर रेलवे के जम्मू-श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलखंड पर ढलान को स्थिर करने, सुरंगों की मरम्मत और पुलों के सुरक्षा कार्यों के लिए 238 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस रेलखंड की दीर्घकालिक सुरक्षा और विश्वसनीयता को मजबूत करना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह देश के सबसे दुर्गम इलाकों में सुरक्षित और भरोसेमंद रेल संपर्क सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कटिंग, पुल और सुरंगों का विस्तृत आकलन करने के बाद सुरक्षा एवं पुनर्वास कार्यों को मंजूरी दी गई है। परियोजना के तहत ढलान को स्थिर करना, सुरंगों से पानी रिसने की समस्या का समाधान, पुलों के सुरक्षा कार्य तथा संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा से जुड़े अन्य उपाय शामिल हैं। रेलवे के अनुसार, इन कार्यों से जम्मू-श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा रेलखंड की संरचनात्मक मजबूती और परिचालन सुरक्षा में उल्लेखनीय सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि यह रेलखंड कठिन भूभाग, प्रतिकूल भूवैज्ञानिक परिस्थितियों और मौसम की चरम घटनाओं के कारण लंबे समय से इंजीनियरिंग और परिचालन चुनौतियों का सामना करता रहा है।

अब पुलिस पर हाथ उठाया तो मिलेगी कठोर सजा

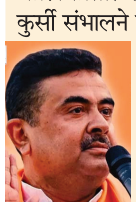

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद सुवेंदु (शुभेंदु) अधिकारी ने राज्य के उपद्रवियों को अब तक की सबसे कड़ी और खुली चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री ने हावड़ा में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोटूक शब्दों में कहा कि अब बंगाल में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेगी। पुलिस और राज्य के गृह मंत्री के तौर पर अपनी आखिरी चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम की यह तीखी प्रतिक्रिया कोलकाता के पार्क सर्कस तिलजला इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ हुई बुलडोजर कार्रवाई के दौरान भड़की हिंसा के बाद आई है। वहां प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया और वाहनों में तोड़फोड़ की थी। इस घटना पर सख्त रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वह दिन चले गए जब पुलिस के लोग घायल होते थे और गृह मंत्री एसी कमरे में बैठकर तमाशा देखते थे। उन्होंने उपद्रवियों को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि अगर अब किसी ने पुलिस पर हाथ उठाया, तो उसे कठोरतम सजा भुगतनी होगी। मुख्यमंत्री ने पुलिस बल का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें कानून हाथ में लेने वालों से निपटने की पूरी छूट दे दी है। पश्चिम बंगाल के राजनीतिक विश्लेषक इसे सीएम सुवेंदु अधिकारी का योगी स्टाइल मॉडल मान रहे हैं।

आम आदमी पर महंगाई की डबल मार: पेट्रोल-डीजल फिर हुआ महंगा

नई दिल्ली। देश में महंगाई के बीच आम लोगों को एक और बड़ा झटका लगा है। तेल कंपनियों ने मंगलवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी कर दी। नई दरों के मुताबिक पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम में करीब 90 पैसे प्रति लीटर तक इजाफा किया गया है। पांच दिनों के भीतर ईंधन कीमतों में यह दूसरी बढ़ोतरी है, जिससे आम जनता की चिंता और बढ़ गई है। इससे पहले पिछले शुक्रवार को भी पेट्रोल और डीजल के दाम में करीब 3 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ोतरी की गई थी। लगातार बढ़ती कीमतों का असर अब सीधे लोगों की जेब पर दिखाई देने लगा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रांसपोर्टेशन लागत बढ़ने से आने वाले दिनों में सब्जियों, दूध, राशन और अन्य जरूरी सामानों के दाम भी बढ़ सकते हैं।

महानगरों में पेट्रोल-डीजल के नए दाम : नई कीमतों के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 98.64 रुपये प्रति लीटर और डीजल 91.58 रुपये प्रति लीटर हो गया है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपये और डीजल 94.08 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 109.70 रुपये और डीजल 96.07 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है, जबकि चेन्नई में पेट्रोल 104.49 रुपये और डीजल 96.11 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है।

मानवाधिकार संस्थानों को बेवजह के मुकदमों से बचने के लिए क्षेत्राधिकार की स्पष्टता जरूरी है: न्यायमूर्ति रामासुब्रमणियन

एजेंसी। नई दिल्ली

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमणियन ने मंगलवार को कहा कि मानवाधिकार संस्थानों को कानून (मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम) के दायरे और अपने तय अधिकार क्षेत्र में रहकर ही काम करना चाहिए ताकि बेवजह के मुकदमों से बच सकें। वी. रामासुब्रमणियन ने नई दिल्ली स्थित एनएचआरसी परिसर में राज्य मानवाधिकार आयोगों (एसएचआरसी), अपने विशेष प्रतिवेदकों और विशेष पर्यवेक्षकों के साथ 'वर्चुअल मोड' में आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन पर यह बात कही। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य नीतिगत उद्देश्यों और जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन के बीच के अंतर को पाटना तथा मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण विकसित करना था। रामासुब्रमणियन ने कहा, "मानवाधिकार संस्थानों को 'मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम' के तहत दी गई परिभाषाओं और अपने निर्धारित क्षेत्राधिकार के भीतर ही काम करना चाहिए। जब अधिकार क्षेत्र बिल्कुल साफ होता है, तो बेवजह के मुकदमों से बचा जा सकता है और आयोग ज्यादा बेहतर व असरदार तरीके से काम कर पाएंगे। उन्होंने मामलों के दोहराव से बचने और बेहतर समन्वय के लिए सभी राज्य आयोगों से अपने कामकाज को डिजिटल बनाने और एनएचआरसी के एकीकृत एचआरसीनेट पोर्टल से जुड़ने का आग्रह किया। एनएचआरसी के सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन सारंगी ने इस संवाद को दोनों मंचों के बीच समन्वय मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। एनएचआरसी के सदस्य विजया भारती सयानी ने एसएचआरसी से प्रभावित समुदायों के साथ जुड़ाव बढ़ाने और जमीनी स्तर पर क्षेत्रीय दौरों में तेजी लाने का आग्रह किया। साथ ही, उन्होंने जन सहायता के लिए संपर्क विवरण प्रदर्शित करने की कर्नाटक सरकार की पहल की सराहना की। एनएचआरसी के महासचिव भरत लाल ने अपने उद्घाटन भाषण में बताया कि मानवाधिकार एक जटिल विषय है जिसके लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने पिछले 5 वर्षों में ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से प्राप्त 4.28 लाख शिकायतों का विश्लेषण प्रस्तुत किया, जो मुख्य रूप से कई श्रेणियों से संबंधित हैं।

अमेरिका ने भारत के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर सहायता सौदे को मंजूरी दी

नई दिल्ली। अमेरिका के विदेश विभाग ने भारत को अपाचे हेलीकॉप्टर, सपोर्ट सेवाएं और संबंधित उपकरणों की संभावित विदेशी सैन्य बिक्री (एफएमएस) को मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित लागत 198.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। अमेरिकी विदेश विभाग के राजनीतिक-सैन्य मामलों के ब्यूरो की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, भारत सरकार ने एएच-64ई अपाचे हेलीकॉप्टरों के रखरखाव और संचालन सहायता सेवाएं, अमेरिकी सरकार और ठेकेदारों की इंजीनियरिंग, तकनीकी एवं लॉजिस्टिक सहायता सेवाएं, तकनीकी डेटा एवं प्रकाशन, कर्मियों का प्रशिक्षण तथा अन्य संबंधित लॉजिस्टिक और प्रोग्राम सहायता सेवाओं की खरीद का अनुरोध किया है। अमेरिका ने कहा कि यह प्रस्तावित बिक्री भारत-अमेरिका रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने तथा एक प्रमुख रक्षा साझेदार की सुरक्षा क्षमता बढ़ाने में मदद करेगी। बयान में कहा गया कि भारत हिंद-प्रशांत और दक्षिण एशिया क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता, शांति और आर्थिक प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति बना हुआ है। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, प्रस्तावित सौदे से भारत की वर्तमान और भविष्य के खतरों से निपटने की क्षमता मजबूत होगी, उसकी घरेलू सुरक्षा बेहतर होगी और क्षेत्रीय खतरों के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी।

कतर, सऊदी और यूएई के अनुरोध पर ट्रंप ने ईरान पर हमले को टाला, बातचीत तेज

वाशिंगटन। ईरान-अमेरिका के युद्ध में अब तक लग रहा था कि जल्दी ही दोनों पक्ष फिर आमने-सामने आ जाएंगे। अमेरिका की ओर से लगातार धमकियां मिल रही थीं, तो ईरान भी उनका जवाब दे रहा था। ऐसे में माना जा रहा था कि जल्द ही खाड़ी में फिर मिसाइलें और बम बरसेंगे। हालांकि अब राहत भरी खबर आई है कि कम से कम अमेरिका आगे के हमलों को टालने की योजना बना रहा है। पहले से ही दुनियाभर में तेल को लेकर हाहाकार मचा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान पर प्रस्तावित हमला फिलहाल टाल दिया है। ट्रंप ने कहा कि कतर, सऊदी अरब और यूएई के अनुरोध पर यह फैसला लिया गया है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अब ईरान के साथ गंभीर बातचीत चल रही है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने साफ कहा कि बातचीत का मतलब आत्मसमर्पण नहीं है। उन्होंने कहा कि तेहरान सम्मान, ताकत और अपने राष्ट्रीय अधिकारों की रक्षा करते हुए बातचीत में शामिल हुआ है। इस बीच इजराइल और लेबनान के बीच संघर्ष जारी है।

नितिन गडकरी और रेखा गुप्ता ने किया एनएच-148एनए परियोजना का निरीक्षण

एजेंसी। नई दिल्ली

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने वाली महत्वाकांक्षी एनएच-148एनए के अंतर्गत डीएनडी महारानी बाग से जैतपुर पुश्ता रोड तथा फरीदाबाद-बल्लभगढ़ बाईपास खंड तक निर्माणाधीन छह लेन एक्सेस कंट्रोल्ड राजमार्ग परियोजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, अजय टम्टा, सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी तथा पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी भी मौजूद रहे। डीएनडी की ओर से आगे बनने वाले इस लगभग नौ किलोमीटर लंबे हिस्से में करीब 7.50 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जबकि आगरा नहर के आगे जैतपुर पुश्ता रोड तक लगभग 1.50 किलोमीटर सड़क सतह पर विकसित की गई है। निरीक्षण के दौरान केंद्रीय मंत्री ने फरीदाबाद को नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ने वाले ग्रीनफील्ड द्रुतमार्ग परियोजना की प्रगति का भी अवलोकन किया। कार्यक्रम के बाद उन्होंने डीएनडी महारानी बाग छोर पर मीडिया को परियोजना से संबंधित जानकारी दी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से विकसित की जा रही इस परियोजना की कुल लंबाई लगभग 59.063 किलोमीटर है तथा इसकी अनुमानित लागत लगभग 4463 करोड़ रुपये है।

होर्मुज से आई अच्छी खबर, 55 मालवाहक जहाज गुजरे इसमें तेल-गैस के टैंकर भी

एजेंसी। नई दिल्ली

रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने हाल में ज्यादा जहाज इस मार्ग से गुजरने की दी अनुमति

ईरान-अमेरिका युद्ध के बाद से पूरी दुनिया में तेल-गैस के बढ़ते हुए दाम को लेकर हाहाकार मचा है। यहां तक कि भारत में भी लगातार तेल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। इसी बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से खुशखबरी मिली है कि हफ्तेभर में यहां से शिप्स की सबसे बड़ी संख्या गुजरी है। रिपोर्ट के मुताबिक होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों की संख्या में फिर से बढ़ोतरी देखी गई है। समुद्री निगरानी कंपनी के आंकड़ों के मुताबिक 11 मई से 17 मई के बीच हर सप्ताह करीब 55 मालवाहक जहाज इस रास्ते से गुजरे। इससे पहले युद्ध के दौरान यह संख्या गिरकर सिर्फ 19 जहाज रह गई थी, जो संघर्ष शुरू होने के बाद का सबसे निचला स्तर था। बता दें 28 फरवरी को अमेरिका-इजराइल ने संयुक्त रुप से ईरान पर किए हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव काफी बढ़ गया था। इसके जवाब में ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया था, जिससे वैश्विक तेल और गैस बाजारों में भारी उथल-पुथल मच गई थी। जहाजों की आवाजाही रुकने से दुनिया भर में ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई थी। अब ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि समुद्री यातायात धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक रिवोल्यूशनरी गाड्र्स ने हाल के दिनों में ज्यादा जहाजों को इस मार्ग से गुजरने की अनुमति दी है। रिपोर्ट में कहा गया कि सप्ताह की शुरुआत में एक ही दिन में 30 से ज्यादा जहाजों को मंजूरी दी गई। हालांकि ईरानी अधिकारियों का कहना है कि हालात अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हैं और युद्ध से पहले जैसी स्थिति लौटने में समय लगेगा। पिछले सप्ताह गुजरने वाले 55 जहाजों में अलग-अलग प्रकार के मालवाहक पोत शामिल थे। इनमें करीब आधे तेल और अन्य तरल पदार्थ ले जाने वाले टैंकर थे। इसमें तीन बड़े क्रूड ऑयल टैंकर चीन, ओमान और जापान की ओर जा रहे थे।

मेरी गैरमौजूदगी को चुप्पी न समझा जाए, मैं जल्द लौटूंगी अपने देश

नई दिल्ली। मेरी गैरमौजूदगी को चुप्पी न समझा जाए। मैं जल्द अपने देश वापस लौटूंगी। यह कहना है बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना का। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि लगातार अपने देश और लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष कर रही हैं। फिलहाल वो भारत में अपना समय बिता रहीं हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना ने कहा कि 17 मई 1981 उनके जीवन का बेहद भावुक दिन था, जब वह छह साल के निर्वासन के बाद भारत से बांग्लादेश लौटी थीं। उन्होंने कहा कि उस समय भी उनके खिलाफ साजिशें हुई थीं, मुकदमे दर्ज किए गए थे और जान का खतरा था, लेकिन जनता के प्यार और समर्थन ने उन्हें वापस लौटने की ताकत दी। उन्होंने कहा कि इस बार उनकी वापसी किसी तय तारीख पर निर्भर नहीं है, बल्कि बांग्लादेश में लोकतांत्रिक माहौल, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राजनीतिक अधिकारों और कानून के शासन की बहाली पर निर्भर करेगी। हसीना ने दावा किया कि वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक और कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं।

Mfg & mkt by.. ANGEN PHARMACEU-TICALS (OPC) PRIVATE LIMITED

Distributorship ke liye contact Karen .
(9315755133 / ya email Karen)
angenpharmaceuticals@gmail.com

ख़ास ख़बर

टैटू इंडस्ट्री को रेगुलेट करने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। देशभर में टैटू इंडस्ट्री को रेगुलेट करने की मांग को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में टैटू पार्लरों के लिए अनिवार्य लाइसेंस, स्वच्छता मानक, टैटू इंक की जांच और नाबालिगों को माता-पिता की अनुमति के बगैर टैटू बनवाने पर रोक लगाने की मांग की गई है। वकील अभिषेक कुमार चौधरी ने दायर याचिका में मांग की है कि टैटू इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए एक यूनिफॉर्म मानदंड बनाया जाए। याचिका में कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में देश भर में टैटू इंडस्ट्री करीब बीस हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार करती है। इसके बावजूद टैटू इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए कोई स्पष्ट मानदंड तय नहीं किए गए हैं। याचिका में कहा गया है कि टैटू इंडस्ट्री को रेगुलेट नहीं करने की वजह से कई ऐसे लोग हैं, जिन्हें स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। टैटू का इस्तेमाल करने वाले एक ही उपकरण से कई लोगों पर टैटू लगाए जाते हैं। इससे उन्हें खून के ट्रांसमिशन से होने वाले रोग जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और एचआईवी एड्स जैसे गंभीर रोगों का खतरा बढ़ जाता है। याचिका में कई मीडिया रिपोर्ट्स, मेडिकल जर्नल और रिसर्च पेपर्स का हवाला दिया गया है, जिनमें असुरक्षित टैटू पर चिंता जताई गई है। टैटू के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सूईयों और टैटू के रंग खून और शरीर के दूसरे अंगों तक पहुंच जाते हैं। याचिका में टैटू के इंक पर चिंता जताते हुए कहा गया है कि कई इंक में भारी धातु जैसे शीशा, एल्युमिनियम इत्यादि मौजूद होते हैं। याचिका में नाबालिगों को टैटू लगाने पर भी गंभीर चिंता जताई गई है। याचिका में कहा गया है कि नाबालिगों को उनके पिता की सहमति के बिना टैटू लगा दिए जाते हैं। ऐसा करना भारतीय कानून के मुताबिक वैध सहमति की श्रेणी में नहीं आता है।

कांग्रेस ने हरियाणा और अरुणाचल में संगठनात्मक नियुक्तियां कीं

की शान :

नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) विभाग के राज्य अध्यक्ष पद पर चंद्र प्रकाश तथा अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदिवासी कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष पद पर एडवोकेट तामी पांगु की नियुक्ति की है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल की ओर से मंगलवार को जारी अलग-अलग प्रेस विज्ञप्तियों में यह जानकारी दी गई। कांग्रेस अध्यक्ष ने दोनों नेताओं की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दोनों नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

भारतीय रेलवे ने 993 करोड़ रुपये की अराक्कोनम-चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना को मंजूरी दी

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने दक्षिण रेलवे के अरक्कोनम-चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना (68 किमी) को 993 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क में भीड़भाड़ कम करना, यात्री सुविधाओं में सुधार करना और माल परिवहन को मजबूत बनाना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह परियोजना चेन्नई के व्यस्त उपनगरीय रेल नेटवर्क पर भीड़ कम करने, ट्रेनों की समयपालन क्षमता बढ़ाने और परिचालन दक्षता में सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इससे यात्रियों के साथ-साथ माल ढुलाई को भी मजबूती मिलेगी तथा सीमेंट, ऑटोमोबाइल, अनाज, लोहा और इस्पात जैसी प्रमुख वस्तुओं के परिवहन को लाभ होगा। यह रेलखंड चेन्नई समुद्र तट, तांबरम, चेंगलपट्टू और अरक्कोनम को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण चेन्नई उपनगरीय सर्कुलर रेल नेटवर्क का हिस्सा है। वर्तमान में इस एकल रेल लाइन पर क्षमता का अत्यधिक उपयोग हो रहा है और आने वाले वर्षों में यातायात बढ़ने की संभावना को देखते हुए अतिरिक्त रेल अवसंरचना की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।रेल मंत्रालय के अनुसार दोहरीकरण कार्य पूरा होने के बाद ट्रेनों के ठहराव समय में कमी आएगी, समयपालन बेहतर होगा और उपनगरीय रेल सेवाओं की आवृत्ति बढ़ाई जा सकेगी।यह मार्ग महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, श्रीपेरंबदूर, ओरगडम और इरुंगट्टुकोट्टई जैसे प्रमुख औद्योगिक एवं आर्थिक केंद्रों को जोड़ता है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल, सीमेंट और विनिर्माण उद्योगों के लिए भी यह रेलखंड अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कांचीपुरम के निकट प्रस्तावित परंदूर हवाईअड्डा परियोजना भी इस रेलमार्ग के समीप स्थित है, जिससे इसकी रणनीतिक अहमियत और बढ़ गई है। रेलवे के अनुसार इस परियोजना से उपनगरीय और माल ढुलाई संपर्क बेहतर होगा, क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और यात्रियों को तेज, सुरक्षित एवं अधिक विश्वसनीय रेल सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

निगमायुक्त खिरवार ने ओखला लैंडफिल पर बायो-रिमेडिएशन कार्य प्रगति की समीक्षा की

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। निगमायुक्त संजीव खिरवार ने मंगलवार को ओखला लैंडफिल साइट का दौरा कर चल रहे बायो-रिमेडिएशन और अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अधिकारियों ने निगमायुक्त संजीव खिरवार को बायोमाइनिंग गतिविधियों की वर्तमान स्थिति तथा लैंडफिल साइट पर चल रहे कार्यों के बारे में अवगत कराया। खिरवार ने ओखला लैंडफिल साइट पर बायो माइनिंग के कार्य में लगी ट्रामल मशीन के परिचालन को देखा एवं बायो माइनिंग कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि निर्धारित समय सीमा में लैंडफिल साइट पर जमा लीगेसी कचरे को खत्म किया जा सके। निगमायुक्त ने निर्माण एवं विध्वंस कचरे का प्रसंस्करण करने वाले संयंत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने ओखला इंजीनियर्ड सैनिटरी लैंडफिल साइट एवं ओखला कंपोस्ट प्लांट का भी निरीक्षण किया। उन्होंने स्थानीय पार्षद अर्जुन पाल सिंह के साथ लाजपत नगर के कृष्णा मार्केट में स्थित कम्युनिटी सेंटर में चल रहे मरम्मत कार्यों एवं वहां बन रहे वरिष्ठ नागरिक मनोरंजन केंद्र का भी निरीक्षण किया। इस दौरान आयुक्त ने स्थानीय नागरिकों से बातचीत की तथा वहां उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस केंद्र का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए। निगमायुक्त ने कम्युनिटी सेंटर की खाली पड़ी मंजिलों को आउटसोर्स करने के निर्देश दिए ताकि एमसीडी के राजस्व को बढ़ाया जा सके। इस दौरान मध्य क्षेत्र के उपायुक्त शाश्वत सौरभ, प्रमुख अभियंता पीसी मीणा सहित निगम के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

पत्नी से विवाद के बाद युवक ने खुद को लगाई आग, मौत

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। उत्तर-पश्चिमी जिले के जहांगीरपुरी इलाके में सोमवार को वैवाहिक विवाद के चलते एक युवक ने कथित तौर पर खुद को आग लगा ली। गंभीर रूप से झुलसे युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, 18 मई को थाना महेंद्र पार्क पुलिस को पीसीआर कॉल के माध्यम से जहांगीरपुरी में आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वहां दीपांश चौधरी नामक युवक आग से बुरी तरह झुलसी हालत में मिला। पुलिस ने तत्काल युवक को बाबू जगजीवन राम मेमोरियल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उपचार के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। उत्तर-पश्चिमी जिले की पुलिस उपायुक्त आकांक्षा यादव ने मंगलवार को बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मृतक और उसकी पत्नी के बीच काफी समय से वैवाहिक विवाद चल रहा था। दोनों के बीच चल रहे विवाद को लेकर पहले भी मामला सीएडब्लू सेल तक पहुंच चुका था। पुलिस सूत्रों के अनुसार, घटना वाले दिन भी दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी।

दिल्ली बनेगा विश्वस्तरीय यातायात व्यवस्था का उदाहरणः गडकरी

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को डीएनडी-फरीदाबाद-सोहना नियंत्रित प्रवेश राजमार्ग परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में भाजपा सरकार बनने के बाद दिल्ली को यातायात दबाव और जाम की समस्या से मुक्त करने के लिए एक व्यापक योजना बनाई गई थी। इसके तहत नए नियंत्रित राजमार्गों, रिंग रोडों, सुरंगों के माध्यम से दिल्ली को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया जा रहा है। इससे ईंधन की बचत होगी, प्रदूषण कम होगा, माल परिवहन व्यवस्था अधिक सक्षम बनेगी और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा, अजय टम्टा, सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी तथा पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी भी उपस्थित रहे। गडकरी ने कहा कि नए नियंत्रित राजमार्गों, रिंग रोडों, सुरंगों और ऊपरी गलियारों के माध्यम से दिल्ली को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया जा रहा है। विकास परियोजनाओं की लागत बढ़ने के बावजूद कार्यों की गति कम नहीं हुई है और इनसे बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं।उन्होंने कहा कि वर्तमान में दिल्ली में लगभग 1.60 लाख करोड़ रुपये की सड़क मूलभूत ढांचा परियोजनाओं पर काम चल रहा है। अब तक लगभग 87 हजार करोड़ रुपये की लागत से 1050 किलोमीटर लंबाई के सड़क निर्माण कार्य पूरे किए जा चुके हैं। इसके अलावा 13 हजार करोड़ की लागत से 225 किलोमीटर लंबे मार्गों पर निर्माण कार्य जारी है। वहीं, 34,500 करोड़ रुपये की आगामी परियोजनाओं पर भी काम प्रस्तावित है। साथ ही 25 से 30 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में यातायात दबाव कम करना, भीड़ और प्रदूषण घटाना, ईंधन की बचत करना, माल परिवहन लागत कम करना और तेज स्थानीय यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में नए प्राण फूंकने का कार्य केंद्र सरकार और नितिन गडकरी ने किया है। दिल्ली लंबे समय से यातायात और प्रदूषण की गंभीर समस्याओं से जूझ रही थी। यदि केंद्र सरकार और सड़क परिवहन मंत्रालय ने इतने बड़े स्तर पर नियंत्रित राजमार्गों तथा अन्य सड़क परियोजनाओं का निर्माण नहीं कराया होता तो दिल्लीवासियों के लिए हालात और अधिक कठिन हो जाते। पिछले 12 वर्षों में केवल दिल्ली के लिए लगभग 1.31 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं दी गई हैं, जिनसे राजधानी की यातायात व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन आया है।रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली को विश्वस्तरीय, हरित और टिकाऊ यातायात व्यवस्था का उदाहरण बनाने के लिए केंद्र ने जो प्रयास किए हैं, वे ऐतिहासिक हैं। इन परियोजनाओं ने न केवल यातायात दबाव को कम किया है, बल्कि प्रदूषण घटाने और ईंधन की बचत करने में भी मदद की है। डीएनडी-फरीदाबाद-सोहना नियंत्रित प्रवेश राजमार्ग परियोजना का निर्माण कार्य 11 जनवरी 2022 को शुरू हुआ था। इस लगभग नौ किलोमीटर लंबे हिस्से में 7.50 किलोमीटर लंबा ऊपरी गलियारा और 1.50 किलोमीटर सड़क सतह पर विकसित की जा रही है। परियोजना का सबसे जटिल हिस्सा आगरा नहर पर बनाया जा रहा 140 मीटर लंबा इस्पात नेटवर्क मेहराब पुल है। अधिकारियों के अनुसार यह पुल आधुनिक तकनीकों से तैयार किया जा रहा है, जिसमें इस्पात मेहराब ढांचा, परस्पर क्रॉस व्यवस्था वाले हैंगर केबल, टाई बीम, क्रॉस गर्डर तथा मिश्रित डेक पट्टिका शामिल हैं। पुल को भूकंप सुरक्षा, अधिक मजबूती और दीर्घकालिक उपयोग को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है।भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विकसित की जा रही इस परियोजना की कुल लंबाई लगभग 59.063 किलोमीटर है और इसकी अनुमानित लागत लगभग 4463 करोड़ रुपये है। यह छह लेन नियंत्रित प्रवेश राजमार्ग दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोहना को जोड़ते हुए दिल्ली-मुंबई राजमार्ग तथा आगामी नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जेवर तक निर्बाध संपर्क उपलब्ध कराएगा। परियोजना पूरी होने के बाद यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी, यातायात प्रवाह बेहतर होगा और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी।

इंस्टाग्राम पर हथियार लहराकर दहशत फैलाने वाला 'मोहित उर्फ बाबा गैंग' पकड़ा गया

लोकतंत्र की शान

शांति सेवा न्याय

Delhi Police
SHANTI SEWA NYAYA

नई दिल्ली। उत्तर-पश्चिमी जिला पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम ने सोशल मीडिया पर हथियार लहराकर इलाके में दहशत फैलाने वाले 'मोहित उर्फ बाबा गैंग' का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने हत्या के एक मामले में वांछित चल रहे गैंग सरगना समेत चार आरोपितों और एक नाबालिग को पकड़ा है। उनके कब्जे से दो अत्याधुनिक अवैध पिस्टल, तीन जिंदा कारतूस और वारदात में इस्तेमाल स्कूटी बरामद की गई है। पुलिस का कहना है कि समय रहते कार्रवाई कर संभावित गैंगवार और हत्या की वारदात को टाल दिया गया। उत्तर पश्चिमी जिले की पुलिस उपायुक्त आकांक्षा यादव ने मंगलवार को बताया कि जहांगीरपुरी निवासी शोएब ने शिकायत दी थी कि उसके भाई जुनैद कुरैशी की हत्या के पुराने विवाद को लेकर मोहित उर्फ बाबा उसे लगातार इंस्टाग्राम कॉल के जरिए धमकी दे रहा था। आरोप है कि आरोपित ने सोशल मीडिया पर अपने साथियों के साथ फायरिंग करते हुए वीडियो भी अपलोड किया था। इतना ही नहीं, 11 मई को दो युवक पिस्टल लेकर शिकायतकर्ता के घर के बाहर पहुंचे और फायरिंग की कोशिश की। मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद जिले की स्पेशल स्टाफ टीम ने जांच शुरू की। पुलिस लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हथियारबाजी वाले वीडियो और गैंग की गतिविधियों पर नजर रख रही थी। तकनीकी जांच और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस को पता चला कि आरोपित शकूरपुर इलाके में आने वाला है। इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर मोहित उर्फ बाबा को पकड़ लिया। तलाशी में उसके पास से एक अवैध पिस्टल और तीन जिंदा कारतूस बरामद हुए। पूछताछ में उसने अपने साथियों राधे और शांतनु उर्फ चिका के नाम बताए। बाद में पुलिस ने दोनों को भी दबोच लिया और एक किशोर को पकड़ा। राधे की निशानदेही पर दूसरी पिस्टल बरामद हुई। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपित सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ वीडियो डालकर इलाके में अपना दबदबा बनाना चाहते थे। गैंग के सरगना मोहित उर्फ बाबा के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, झपटमारी और आर्म्स एक्ट के कई मामले पहले से दर्ज हैं।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सौजन्य से राज्य अल्पसंख्यक आयोग की संयुक्त कॉन्फ्रेंस आयोजित

लोकतंत्र की शान

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सौजन्य से नई दिल्ली चाणक्यपुरी में स्थित सुशमा स्वराज ऑडीटोरियम के सभागार में राज्य अल्पसंख्यक आयोग की संयुक्त कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई जिसमें मुख्य अतिथी अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरन रिजजू, राज्य अल्पसंख्यक कार्यमंत्री जॉर्ज कुरियन और अन्य राज्यों के अल्पयंख्क मंत्री उपस्थित हुए। इस अवसर पर कॉन्फ्रेंस में आए सभी अतिथी गणों को फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य अल्पसंख्यक आयोगों की समस्या और उनके लाभकारी कार्यों की पूर्ण जानकारी लेनी थी। कॉन्फ्रेंस में संबोधित करते हुए तेलंगाना सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री व पूर्व क्रिकेट कप्तान मो. अज़हरउद्दीन ने कहा तेलंगाना सरकार में अल्पसंख्यकों उत्थान के लिए जो कार्य किये गए हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं, तेलंगाना सरकार अपने राज्य के फंड से अल्पसंख्यकों को जो फंड देती है वो लाभकारी कार्यों के लिए बहुत कम है। अल्पसंयक केन्द्रीय मंत्री किरन रिजजू से आग्रह है वो तेलंगाना सरकार के अल्पसंख्यक फंड में बढ़ोतरी करे ताकि तेलंगाना सरकार अल्पसंख्यकों के लिए कल्याणकारी कार्य कर सके। झारखंड के अल्पसंख्यक मंत्री हफ़ीजुल हसन ने कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का नारा ''सबका साथ सबका विकास'' वो नारा झारखंड में बेअसर साबित हो रहा है, गत छः वर्षों से झारखंड सरकार को अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए कोई फंड नहीं मिला यही कारण है झारखंड के अल्पसंख्यक समुदाय उन्नती की राह से बहुत पीछे है। झारखंड सरकार की तरफ से मेरा अल्पसंख्यक केन्द्रीय मंत्री जी से अनुरोध है झारखंड सरकार का अल्पसंख्यक फंड शीघ्र ही दिया जाए ताकि झारखंड सरकार अपने राज्य में अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए कार्य कर सके। इसके अलावा बिहार सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री ज़मा खान और उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आज़ाद अन्सारी ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए अपनी राज्य सरकार की सरकारी योजनाओं पर रोशनी डालते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का गुणगान किया। अंत में अल्पसंख्यक कार्यमंत्री किरन रिजजू ने कहा भारत में अल्पसंख्यक समुदाय दूसरे देशों के मुकाबले सुरक्षित और विकसित हैं यहीं कारण है म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, अफ़गानिस्तान आदि इन देशों के अल्पसंख्यक समुदाय भारत में आकर निवास करना चाहते हैं क्योंकि इन देशों में अल्पसंख्यकों पर निरंतर अत्याचार होते रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सत्ता में आते ही ''सबका साथ सबका विकास'' का जो नारा दिया था उसके तहत अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदाय के लिए 140 लाभकारी योजनाएं लागू कीं जिसका लाभ दोनों समुदाय की जनता को मिल रहा है। अल्पसंख्यकों को मिलने वाली स्कॉलरशिप जो कई वार्षों से बंद है भ्रष्टाचार के कारण सी.बी.आई की जांच चल रही है। सी.बी.आई बहुत जल्द जांच पूरी करके इसकी रिपोर्ट उच्च न्यायालय को सोंपेगी। न्यायालय के आदेश के बाद स्कॉलरशिप पुनः जारी की जाएगी। भारत के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उनके अधिकारों के लिए सरकार वचनबद्ध है। कॉन्फ्रेंस में अल्पसंख्यक समुदाय के स्पीकरों ने जनता के प्रश्नों के उत्तर दिये। अंत में आयोग की सचिव अल्का उपाध्याय ने कार्यक्रम में आए हुए सभी अथितियों और जनता का धन्यवाद व्यक्त किया। इस अवसर पर उपस्थित लोग जो इस प्रकार हैं। आयोग सदस्य मुनव्वरी बेगम, ब्रजेस देसाई, पूर्व आयोग उपाध्यक्ष आतिफ़ रशीद, आयोग की एडवायज़री पैनल सदस्य मो. रियाज़ व उनकी टीम तारिक़ प्रवेज़, मो. आदिल, शाहिद रंगरेज़, रियाज़ुद्दीन, एडवोकेट सद्दाम मुजीब, एच.एस. लांबा, डा. शंकर लाल इत्यादी।

प्रधानमंत्री पर बरसे राहुल गांधी- देश में जबरदस्त आर्थिक तूफान आने वाला है, सबसे ज्यादा चोट हिंदुस्तान के मजदूरों, किसानों, युवाओं, छोटे व्यापारियों को लगेगी

लोकतंत्र की शान

नई दिल्लीः लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आर्थिक संकट की चेतावनी देते हुए कहा कि देश में जबरदस्त आर्थिक तूफान आने वाला है, जिसकी सबसे ज्यादा चोट मजदूरों, किसानों, युवाओं और छोटे व्यापारियों को लगेगी। अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में आयोजित ग्राम विकास संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि वह सरकार को लगातार आगाह कर रहे हैं कि देश में आर्थिक तूफान आने वाला है, महंगाई बढ़ने वाली है, लोगों की रक्षा कीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आम जनता की परवाह नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री जनता से सोना न खरीदने, इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करने और विदेश नहीं जाने की अपील करते हैं, लेकिन इसके तुरंत बाद स्वयं विदेश दौरे पर निकल जाते हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री विभिन्न देशों में जाकर भी अडानी-अंबानी की मदद की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि देश के किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों की जो भी जमा-पूंजी थी, उसे नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी और गलत तरीके से लागू की गई जीएसटी के जरिए छीन लिया। आज देश के बंदरगाह, हवाई अड्डे, बिजली और रक्षा क्षेत्र समेत सब कुछ अडानी-अंबानी के हाथों में सौंप दिया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि मीडिया पर अडानी-अंबानी का पूरा नियंत्रण है। उन्होंने यह भी कहा कि अडानी और अंबानी सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी की मार्केटिंग करते हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी देश के युवाओं को रील देखने की सलाह देते हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी के निधन पर शोक सभा आयोजित, डॉ. जया शुक्ला जी ने भी दी भावभीनी श्रद्धांजलि

लोकतंत्र की शान

नई दिल्लीः उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी रहे मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद एवं राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति है। उनका संपूर्ण जीवन राष्ट्रसेवा, अनुशासन, ईमानदारी और सादगी का प्रेरणादायी उदाहरण रहा। 91 वर्षीय मेजर जनरल खंडूरी जी लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। भारतीय सेना में उत्कृष्ट सेवाएं देने के उपरांत उन्होंने राजनीति में भी स्वच्छ छवि, दृढ़ नेतृत्व और जनसेवा के उच्च आदर्श स्थापित किए। उत्तराखंड के विकास में उनका योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। उनके निधन से देश ने एक सच्चे राष्ट्रभक्त, ईमानदार प्रशासक और दूरदर्शी नेता को खो दिया है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा शोकाकुल परिजनों एवं समर्थकों को यह असीम दुःख सहन करने की शक्ति दें। इस अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में डॉ. जया शुक्ला जी ने भी मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी जी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि खंडूरी जी का संपूर्ण जीवन राष्ट्रहित, निष्ठा और जनसेवा के लिए समर्पित रहा। उनकी ईमानदार कार्यशैली, सादगी और कर्तव्यनिष्ठा सदैव आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।

भावपूर्ण श्रद्धांजलि -मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी जी अमर रहें। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शांति प्रदान करें।

पंजाब सरकार को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का नोटिस

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने सोमवार को जनगणना से संबंधित शिकायत पर संज्ञान लेते हुए पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। यह शिकायत राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष हरदीप सिंह गिल द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना को दी गई थी। शिकायत में कहा गया है कि जनगणना प्रक्रिया में वाल्मीकि समुदाय के संदर्भ में अपमानजनक शब्दों के उपयोग से समुदाय में रोष है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आयोग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित विभागों को नोटिस जारी किया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने जनगणना संचालन निदेशालय, पंजाब के निदेशक तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग, पंजाब सरकार के प्रमुख सचिव को 15 दिनों के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना ने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जातियों के सम्मान, अधिकार और गरिमा की रक्षा आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आयोग इस विषय पर प्राप्त रिपोर्ट और कार्रवाई के आधार पर आगे आवश्यक कदम उठाएगा।उल्लेखनीय है कि पंजाब में मादक पदार्थ और सामाजिक-आर्थिक जनगणना का पहला चरण चल रहा है। इसके तहत अधिकारियों द्वारा घर-घर जाकर मकानों की स्थिति, सुविधाओं और संपत्ति से जुड़े 33 सवाल पूछे जा रहे हैं। पहला चरण (हाउस लिस्टिंग और आवास जनगणना) दो भागों में विभाजित था। इसके तहत स्व-गणना की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पूरी की गई। वहीं, 15 मई से 13 जून तक कर्मचारी घर-घर जाकर डेटा संग्रह कर रहे हैं।

हावड़ा-दिल्ली कॉरिडोर पर क्षमता बढ़ाने के लिए किउल-झाझा तीसरी रेल लाइन परियोजना को मंजूरी

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने हावड़ा-दिल्ली रेल मार्ग पर क्षमता विस्तार और परिचालन दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से 54 किलोमीटर लंबी किउल-झाझा तीसरी रेल लाइन परियोजना को 962 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दी है। यह भारतीय रेलवे के अति व्यस्त यातायात वाले नेटवर्क का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इससे पूर्वी तथा उत्तरी भारत में यात्री एवं माल परिवहन को मजबूती मिलने की उम्मीद है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि किउल-झाझा तीसरी लाइन परियोजना हावड़ा-दिल्ली कॉरिडोर पर क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करेगी तथा ट्रेनों की समयपालन क्षमता और परिचालन लचीलेपन में सुधार लाएगी। अतिरिक्त रेल लाइन से यात्री और मालगाड़ियों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित होगी और क्षेत्रीय औद्योगिक विकास तथा व्यापार संपर्क को भी बढ़ावा मिलेगा।रेल मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में किउल और झाझा के बीच मौजूदा दोहरी रेल लाइन अपनी आदर्श क्षमता से अधिक दबाव में संचालित हो रही है। आने वाले वर्षों में इस मार्ग पर यातायात और बढ़ने की संभावना को देखते हुए अतिरिक्त अवसंरचना की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। प्रस्तावित तीसरी लाइन परियोजना से लाइन क्षमता में वृद्धि होगी, भीड़भाड़ कम होगी और यात्री तथा मालगाड़ियों की आवाजाही अधिक सुगम बन सकेगी। इससे पटना और कोलकाता के बीच संपर्क बेहतर होगा, साथ ही उत्तरी और पूर्वी भारत के प्रमुख औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक केंद्रों से जुड़ी माल ढुलाई को भी मजबूती मिलेगी। यह रेलखंड कोलकाता और हल्दिया बंदरगाहों को रक्सौल तथा नेपाल से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा बरह एसटीपीपी, जवाहर एसटीपीपी और बीरगंज आईसीडी जैसे प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठानों से जुड़े भारी माल यातायात का संचालन भी इसी मार्ग से होता है। रेलवे के अनुसार इस रणनीतिक कॉरिडोर पर बढ़ती यातायात मांग को देखते हुए यह परियोजना दीर्घकालिक आधारभूत संरचना समर्थन प्रदान करेगी। अतिरिक्त वहन क्षमता और बेहतर संपर्क से लॉजिस्टिक्स संचालन अधिक कुशल होगा, भीड़भाड़ कम होगी और पूर्वी एवं उत्तरी भारत के प्रमुख आर्थिक केंद्रों के बीच रेल परिवहन अधिक विश्वसनीय बन सकेगा।

संक्षिप्त समाचार

कुईया में अधेड़ का शव मिलने से फैली सनसनी

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा, हसनपुर: मंगलवार को नगर क्षेत्र में अधेड़ का शव कुईया में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता ते चले कि नगर के मोहल्ला कायस्थान चामुंडा रोड निवासी खालिद पहलवान पुत्र नूर अहमद दीपपुर मार्ग से सटे एक आम के बाग में झोपड़ी डालकर रहता था। खालिद का एक ही बेटा है जो मुंबई में सैलून पर रहता है तथा एक बेटी भी है जिसकी शादी हो गई है। रहरा बस स्टैंड चौराहा के समीप खालिद टूटे-फूटे हुए मरीजों का इलाज करता था। सोमवार की रात वह आम के बाग में सोने के लिए गया था। मंगलवार की दोपहर के समय किसी ने खालिद पहलवान के छोटे भाई राशिद को घर आकर बताया तेरे भाई की लाश कुइयां में पड़ी हुई है। सूचना मिलते ही कोतवाल राजेश कुमार तिवारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गये। अनुमान लगाया जा रहा है कि खालिद पहलवान रात किसी समय कुइया में गिर गये जिससे उनकी मौत हो गई। उनका शव भी अकड़ गया था। परिजनों एवं मोहल्ले के लोगों के मुताबिक खालिद बहुत ही मिलन सार था उसकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

रामपुर में रेलवे कर्मी का शव पेड़ से लटका मिला, इलाके में मचा हड़कंप

मंडल प्रभारी अवनीत कुमार शर्मा, रामपुर। उत्तर प्रदेश/जनपद के थाना शहजादनगर क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब इटावा निवासी एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका हुआ मिला। मृतक की पहचान सुनील कुमार के रूप में हुई है, जो ककरोआ गांव में किराए पर रहकर जीवनयापन कर रहा था। बताया जा रहा है कि सुनील कुमार रेलवे विभाग में गेंगमैन (गैंगमैन) के पद पर कार्यरत था और सरकारी कर्मचारी था। पुलिस को सूचना मिली कि थाना शहजादनगर क्षेत्र स्थित स्वाति मैथॉल प्लांट के पीछे नहर के किनारे एक पेड़ पर युवक का शव लटका हुआ है। सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाकर कब्जे में ले लिया। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, हालांकि मौत के कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है।

रामपुरः तहसील सदर में भ्रष्टाचार का आरोप, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने आए लोगों से खुलेआम वसूली का मामला

मंडल प्रभारी अवनीत कुमार शर्मा, रामपुर। उत्तर प्रदेश/जनपद रामपुर की तहसील सदर से भ्रष्टाचार का गंभीर मामला सामने आया है। तहसील कार्यालय में तैनात एक संविदा कर्मी नेकपाल पर आरोप है कि वह जन्म प्रमाण पत्र बनवाने आए लोगों से खुलेआम 100 रुपये की वसूली कर रहा है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि जो व्यक्ति पैसे नहीं देता, उसे किसी न किसी कमी का बहाना बनाकर आवेदन वापस कर दिया जाता है और बार-बार परेशान किया जाता है। इससे आम जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और सरकारी कार्यों में रिश्वतखोरी बढ़ती जा रही है। बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से पोटल पर भेजी गई ।कि इस मामले की शिकायत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुरादाबाद मंडल आयुक्त (कमिश्नर) तथा रामपुर जिलाधिकारी (डीएम) को भी भेजी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शिकायतें भेजने के बावजूद कार्रवाई न होना, प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। लोगों ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी कर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि तहसील कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लग सके। अब सवाल यह उठ रहा है कि इतने उच्च स्तर पर शिकायत भेजे जाने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? जनता प्रशासन से जल्द कार्रवाई की उम्मीद लगाए बैठी है।

कटघर रामगंगा रेलवे पुल पर बुजुर्ग महिला ने किया आत्महत्या का प्रयास, पत्रकार ने बचाई जान

मंडल प्रभारी अवनीत कुमार शर्मा, मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश/मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र स्थित रामगंगा रेलवे पुल पर एक बुजुर्ग महिला आत्महत्या का प्रयास करती हुई पुल से लटकी नजर आई। गनीमत रही कि सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले पत्रकार श्रीपाल सिंह राणा की नजर महिला पर पड़ गई। बताया जा रहा है कि महिला पुल से नीचे कूदने की कोशिश कर रही थी। स्थिति बेहद खतरनाक थी — ऊपर से ट्रेन आने का खतरा था और नीचे गिरने पर जान जा सकती थी। श्रीपाल सिंह राणा ने तुरंत हिम्मत दिखाते हुए अपने दो साथियों को बुलाया और तीनों ने अपनी जान जोखिम में डालकर महिला को पुल से ऊपर खींच लिया, जिससे उसकी जान बच गई। बुजुर्ग महिला ने बताया कि दो दिन पहले उनके बेटे की बहू की मौत हो गई थी, जिससे वह बेहद दुखी और हताश थीं। इसी मानसिक तनाव में वह आत्महत्या करने पहुंच गई थीं। बाद में लोगों ने महिला को समझाया और शांत कराया। इसके बाद महिला को सुरक्षित ऑटो से उसके घर भेज दिया गया।

हजरतनगर गढ़ी पुलिस का बड़ा एक्शनः वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार, अपराधियों में मचा हड़कंप

सम्भल : जनपद सम्भल के थाना हजरतनगर गढ़ी पुलिस ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सम्भल कृष्ण कुमार विश्नोई के निर्देशन एवं उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में की गई। पुलिस टीम ने दौराने गश्त एवं वारंटी अभियुक्तों की तलाश के दौरान ग्राम पोटा निवासी सुरेन उर्फ सुरेन्द्र पुत्र मटरूलाल को गिरफ्तार किया। अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा संख्या 1892/25, धारा 147, 148, 149, 323, 429, 504 एवं 506 भादवि के तहत कार्रवाई चल रही थी। गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त को माननीय न्यायालय चन्दौसी भेज दिया गया। इस सराहनीय कार्रवाई में थाना हजरतनगर गढ़ी के उपनिरीक्षक मोहम्मद शाह फैसल, कांस्टेबल अनिल कुमार एवं कांस्टेबल राहुल कुमार की अहम भूमिका रही। थाना प्रभारी संजय कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम लगातार अपराधियों पर शिकंजा कस रही है।

बकरीद पर्व को लेकर प्रशासन अलर्ट शांति व्यवस्था बनाए रखने के दिए निर्देश

» विकास भवन सभागार में SSP और अधिकारियों संग पीस कमेटी की बैठक संपन्न

लोकतंत्र की शान

(बरेली, उत्तर प्रदेश | संदीप चंद्रा) आगामी ईद-उल-जुहा (बकरीद) पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर मंगलवार को विकास भवन सभागार में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद के प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ विभिन्न धर्मों के गणमान्य नागरिक, धर्मगुरु, जनप्रतिनिधि तथा संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है और पर्व के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी थाना प्रभारियों एवं क्षेत्राधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रमण कर संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में विद्युत विभाग, जल निगम, नगर निगम तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को पर्व के दौरान निर्बाध विद्युत आपूर्ति, स्वच्छ पेयजल व्यवस्था एवं साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों से कहा गया कि कुर्बानी स्थलों के आसपास विशेष सफाई अभियान चलाया जाए तथा कुर्बानी के अवशेषों का सुरक्षित एवं वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण कराया जाए ताकि आमजन को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। प्रशासन की ओर से स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी किसी भी स्थिति में न होने पाए। इसके लिए पुलिस एवं प्रशासनिक टीमों को संयुक्त रूप से निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए लगातार चेकिंग अभियान चलाने की बात कही गई।

नेपाली पर्यावरण प्रेमी यमुना ढाकल ने नजीबाबाद में किया पौधारोपण

साइकिल यात्रा से दे रहीं पर्यावरण संरक्षण का संदेश

लोकतंत्र की शान, खिज़र अहमद

नजीबाबाद। नेपाल से साइकिल यात्रा पर निकली पर्यावरण प्रेमी यमुना ढाकल सोमवार को साहनपुर स्थित राजा चरत सिंह इंटर कॉलेज पहुंचीं, जहां उन्होंने पौधारोपण कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान विद्यालय परिसर में अमरूद, सिल्वर ओक, बरगद और बड़हल के पौधे लगाए गए। यमुना ढाकल ने बताया कि उन्होंने 8 फरवरी को नेपाल के लुंबनी से अपनी साइकिल यात्रा शुरू की थी। यात्रा के दौरान वह गोरखपुर, लखनऊ, अयोध्या, मथुरा, चंडीगढ़, लुधियाना, अमृतसर, सहारनपुर, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, केदारनाथ और बद्रीनाथ होते हुए नजीबाबाद पहुंचीं। इसके बाद वह मुरादाबाद, रामपुर और बरेली होते हुए नेपाल वापस लौटेंगी। उन्होंने कहा कि उनकी इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना और अधिक से अधिक वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना है। विद्यालय पहुंचने पर प्रधानाचार्य प्रदीप कुमार ने बुके देकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर नजीबाबाद वन प्रभाग के रेंजर रामकुमार, डिप्टी रेंजर हरगोविंद सिंह, पूर्व नौसैनिक रविंद्र काकरान, अरुण दीक्षित और योगाचार्य अरुण राजपूत सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

श्री श्याम संकीर्तन महोत्सव की तैयारियां शुरू, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुआ भूमि पूजन

लोकतंत्र की शान, मंडल प्रभारीअवनीत कुमार शर्मा

रामपुर। उत्तर प्रदेश /जनपद रामपुर के मिलक नगर के रामलीला मैदान में आगामी 23 मई को आयोजित होने वाले भव्य 'श्री श्याम संकीर्तन महोत्सव' की तैयारियां हर्षोल्लास के साथ शुरू हो गई हैं। शनिवार को कार्यक्रम स्थल पर आयोजन समिति द्वारा विधि-विधान से भूमि पूजन एवं ध्वज पूजन किया गया। समिति के अध्यक्ष सुनील गुप्ता एवं प्रमुख समाजसेवी प्रिंस गुप्ता ने संयुक्त रूप से मुख्य यजमान के रूप में भूमि पूजन संपन्न किया। पुरोहितों के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्याम बाबा के ध्वज का पूजन कर कार्यक्रम के निर्विघ्न संपन्न होने की कामना की गई। इस दौरान पूरा वातावरण 'जय श्री श्याम' के जयकारों से गुंजायमान हो उठा।

समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि 23 मई को होने वाला यह महोत्सव ऐतिहासिक होगा, जिसके लिए भव्य पंडाल और बाबा का मनमोहक दरबार सजाया जाएगा। इस संकीर्तन में ख्याति प्राप्त भजन गायकों द्वारा बाबा श्याम का गुणगान किया जाएगा। भूमि पूजन के साथ ही कार्यकर्ताओं ने व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है।

इस अवसर पर मुख्य रूप से: जलज गुप्ता, गौरव गुप्ता, परख गुप्ता, वंशज गुप्ता, प्रभात गुप्ता, स्पर्श गुप्ता,अनिल गुप्ता, किंग गुप्ता, शुभम गुप्ता,गुड्डू भार्गव, गोपाल रस्तोगी, प्रमोद महाजन, संजय माहेश्वरी, जितेंद्र गोस्वामी, सुमित शर्मा,वैभव गुप्ता, आशीष कश्यप,सहित भारी संख्या में श्याम प्रेमी और प्रबुद्ध वर्ग के लोग उपस्थित रहे।

स्योडारा के पास गांव डांडा गोबिन्दपुर में पेड़ पर लटका मिला बुजुर्ग का शव, क्षेत्र में फैली सनसनी

लोकतंत्र की शान, मंडल प्रभारी अवनीत कुमार शर्मा

मंडल मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश/बिलारी के बिलारी ब्लॉक क्षेत्र के स्योडारा के निकट स्थित गांव डांडा गोबिन्दपुर में मंगलवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब गांव के बाहर पॉपुलर के पेड़ पर एक 55 वर्षीय बुजुर्ग का शव लटका मिला। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई। मृतक की पहचान गांव निवासी चंद्रपाल सिंह पुत्र राम सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि चंद्रपाल सिंह अपने भाइयों में सबसे बड़े थे। उनके छोटे भाइयों के नाम वीरपाल सिंह, किशनपाल सिंह और जुगल किशोर हैं। परिजनों के अनुसार मृतक अपने पीछे पत्नी विदा देवी, तीन पुत्र और दो पुत्रियां छोड़ गए हैं। बड़े बेटे का नाम राजेश, दूसरे बेटे का नाम मुकेश और सबसे छोटे बेटे का नाम मुनेश है। वहीं बेटियों के नाम मीणा और पुष्पा बताए गए हैं। मृतक के बड़े बेटे राजेश ने बताया कि उनके पिता मंगलवार तड़के करीब तीन से चार बजे के बीच खेत पर जाने की बात कहकर घर से निकले थे। उस समय उनके पास मोबाइल फोन, एक डंडा और धोती थी। सुबह करीब नौ बजे ग्रामीणों ने उनका शव पॉपुलर के पेड़ पर लटका देखा। घटनास्थल से करीब 100 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन, डंडा, धोती और चप्पल भी बरामद हुई हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि मामला आत्महत्या का है या हत्या का। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। घटना के बाद गांव में भय और शोक का माहौल बना हुआ है। मृतक के घर पर पत्नी, बेटियों और अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

बरेली की राजनीति में सक्रिय चेहराः 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटीं सुप्रिया ऐरन

लोकतंत्र की शान

(बरेली उत्तर प्रदेश — संदीप चंद्रा) उत्तर प्रदेश की राजनीति में बरेली का राजनीतिक महत्व हमेशा से खास रहा है। यहां की सियासत में कई बड़े चेहरे समय-समय पर उभरते रहे हैं, जिनमें एक प्रमुख नाम है Supriya Aron। सामाजिक सरोकारों और राजनीतिक सक्रियता के चलते उन्होंने बरेली की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई है। पूर्व महापौर के रूप में शहर के विकास कार्यों से लेकर जनता के बीच मजबूत पकड़ तक, उनका राजनीतिक सफर लगातार चर्चा में रहा है।

महापौर के रूप में बनाई पहचान-सुप्रिया ऐरन वर्ष 2006 से 2011 तक बरेली नगर निगम की महापौर रहीं। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने शहर की सफाई व्यवस्था, सड़क निर्माण, पेयजल और शहरी विकास से जुड़े कई मुद्दों पर कार्य किया। महापौर रहते हुए उन्होंने महिलाओं की भागीदारी और सामाजिक जागरूकता से जुड़े अभियानों में भी सक्रिय भूमिका निभाई।

यही कारण रहा कि शहर की राजनीति में उनका प्रभाव लगातार बढ़ता गया।

कांग्रेस से समाजवादी पार्टी तक का सफर-लंबे समय तक Indian National Congress से जुड़ी रहीं सुप्रिया ऐरन ने कांग्रेस के माध्यम से बरेली की राजनीति में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। उनके पति Praveen Singh Aron भी बरेली से सांसद रह चुके हैं और क्षेत्र की राजनीति में प्रभावशाली चेहरा माने जाते हैं। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सुप्रिया ऐरन और प्रवीण सिंह ऐरन ने कांग्रेस छोड़कर Samajwadi Party का दामन थाम लिया। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने सुप्रिया ऐरन को बरेली कैंट विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। चुनावी मैदान में उन्होंने पूरी मजबूती के साथ प्रचार अभियान चलाया और क्षेत्र में व्यापक जनसंपर्क किया।

2027 विधानसभा चुनाव पर नजर-अब आगामी 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर बरेली की राजनीतिक हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सुप्रिया ऐरन दोबारा विधानसभा टिकट की दावेदारी को लेकर सक्रिय हैं। उनके समर्थक लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और संगठन स्तर पर भी सक्रियता बनाए हुए हैं। सूत्रों की मानें तो कैंट क्षेत्र समेत शहर के कई इलाकों में उनके समर्थक सामाजिक कार्यक्रमों, जनसभाओं और स्थानीय आयोजनों के माध्यम से जनता के बीच पहुंच बना रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बरेली की राजनीति में ऐरन परिवार का प्रभाव अभी भी कायम है और यही कारण है कि आगामी चुनावों में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

जनता के बीच लगातार सक्रियता-सुप्रिया ऐरन समय-समय पर सामाजिक मुद्दों, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और स्थानीय समस्याओं को लेकर जनता के बीच नजर आती रही हैं। राजनीतिक गतिविधियों के अलावा सामाजिक कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी उन्हें आम जनता से जोड़ने का काम करती है। यही वजह है कि समर्थकों के बीच उनकी लोकप्रियता बनी हुई है।

राजनीतिक समीकरणों पर सबकी नजर-2027 विधानसभा चुनाव अभी दूर जरूर है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीतियां बनानी शुरू कर दी हैं। बरेली कैंट सीट पर समाजवादी पार्टी की संभावित रणनीति और टिकट को लेकर चर्चाएं तेज हैं। ऐसे में सुप्रिया ऐरन का नाम एक बार फिर प्रमुख दावेदारों में गिना जा रहा है। आने वाले समय में पार्टी नेतृत्व किसे टिकट देता है, यह भविष्य के राजनीतिक समीकरण तय करेगा, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि बरेली की राजनीति में सुप्रिया ऐरन की सक्रियता आने वाले चुनावों में चर्चा का केंद्र बनी रहेगी।

सनातन जागरण मंच द्वारा पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती मनाई गई

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल
जिला प्रभारी अमरोहा

हसनपुर : सोमवार की देर श्याम सनातन जागरण मंच की एक विशेष बैठक आर्य समाज मंदिर हसनपुर में आयोजित की गई जिसमें महान हिंदू सम्राट वीर योद्धा महाप्रतापी राजा पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती मनाई गई तथा आगामी वीर सावरकर जी की जयंती मनाने पर भी विचार विमर्श हुआ, बैठक के दौरान उपस्थित सनातन जागरण मंच के लोगों ने महान हिंदू सम्राट वीर योद्धा महाप्रतापी राजा पृथ्वीराज चौहान जी के चित्र के सम्मुख पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया, बैठक में वक्ताओं ने महान हिंदू सम्राट वीर योद्धा महाप्रतापी राजा पृथ्वीराज चौहान जी के विषय में विस्तार से बताया, बता ते चले कि बैठक की अध्यक्षता सौरभ गुप्ता ने की तथा मुख्य अतिथि के रूप में सचिन गुप्ता मौजूद रहे, वहीं बैठक में सनातन जागरण मंच की समस्त कार्यकारिणी सदस्य एवं पदाधिकारी मौजूद रहे ।

बड़े मंगलवार पर भारत विकास परिषद मैत्री शाखा ने किया प्रसाद वितरण

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल
जिला प्रभारी अमरोहा

अमरोहाः मंगलवार को अमरोहा में भारत विकास परिषद मैत्री शाखा परिवार के सदस्यों ने ज्येष्ठ माह के बड़े मंगलवार को मंडी चौब चौराहे स्थित मंदिर पर प्रसाद वितरण किया। प्रसाद वितरण से पहले मंदिर में सुबह दस बजे भव्य पूजा अर्चना की गई। और हनुमान चालीसा पाठ के बाद हनुमान जी की आरती की गई। इसके बाद हनुमान जी को पूरी सब्जी और हलुआ का भोग लगाया गया। इसके बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर अनुपम अग्रवाल, मनु कमल गुप्ता, नीरज महेश्वरी, अजय चतुर्वेदी, प्रमोद गुप्ता, राजीव लोचन, बिकास महेश्वरी, अतुल सक्सेना, राजीव लोचन, सुशील कुमार, चारु शर्मा, बर्षा महेश्वरी, काबेरी सक्सेना आदि सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे।

आरटीआई एसोसिएशन भ्रष्ट समाज विरोधीयों से नहीं डरेगी :सुभाष पाल

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल
जिला प्रभारी अमरोहा

हसनपुरः आर टी आई एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सुभाष पाल एवं राष्ट्रीय सचिव बालेश्वर आर्य ने समीक्षा बैठक कर पदाधिकारीयों को प्रशिक्षित करने पर बल दिया, उन्होंने कहा कि आर टी आई कार्यकर्ता प्रशिक्षित होकर विभागों में बेहतर तरीके से समाज हित के कार्य कर सकेंगे । बता ते चले कि सोमवार को देर शाम आर टी आई एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया के प्रदेश प्रभारी भरत लाल प्रजापति के आवास पर आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए संगठन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सुभाष पाल एवं राष्ट्रीय सचिव बालेश्वर आर्य ने उपस्थित पदाधिकारीयों को संबोधित करते हुए कहा कि आर टी आई एसोसिएशन लंबे समय से विभिन्न विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करने के कार्य कर रही है तो वहीं आर टी आई कानून के उचित क्रियान्वयन हेतु कार्यकर्ताओं को समय-समय पर प्रशिक्षित करने का कार्य करती है । उन्होंने आगे कहा कि कुछ समाज विरोधी ताकतें योजनाबद्ध तरीके से कुछ जिला स्तरीय भ्रष्ट अफसरों से मिलकर एसोसिएशन की ख्याति को कलंकित करने का दुसाहस कर रहे हैं , जिनके विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर मुहिम छेड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि हम किसी भी ऐसे समाज विरोधी भ्रष्ट तंत्र से डरने वाले नहीं बल्कि उनका डटकर मुकाबला करने के लिए अपने निष्ठावान, सक्रिय पदाधिकारीयों को प्रशिक्षित करने का कार्य करेंगे । प्रदेश प्रभारी भरत लाल प्रजापति ने कहा कि आर टी आई एसोसिएशन गत 15 वर्षों से निरंतर भ्रष्टाचार के विरुद्ध विभागीय पारदर्शिता और जवाब देही के लिए कार्य कर रही है । उन्होंने कहा कि संगठन का विस्तार करते हुए शीघ्र नए सक्रिय कार्यकर्ताओं को संगठन में स्थान दिया जाएगा । उन्होंने कहा कि हमारे जिलाध्यक्ष पं० मनु शर्मा (एडवोकेट) विभिन्न विभागों से भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए दिन प्रतिदिन नए-नए कीर्तिमान बना रहे हैं । हमें संगठन में ऐसे सक्रिय और निष्ठावान कार्यकर्ता को बल देने की आवश्यकता है । अंत में संगठन के बिस्तर पर बल दिया गया । कार्यक्रम की अध्यक्षता भरत लाल प्रजापति एवं संचालन प्रदेश कार्यालय प्रभारी नसरुद्दीन सैफी ने किया। बैठक में मुख्य रूप से राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सुभाष पाल, राष्ट्रीय सचिव बालेश्वर आर्य , राष्ट्रीय सदस्य पिंटू चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष राहुल शर्मा, प्रदेश प्रशासनिक सचिव नुसरत अली एडवोकेट, प्रदेश सचिव पूरन सिंह राणा, प्रदेश उपाध्यक्ष अजय रस्तोगी, प्रदेश सदस्य विकास, मंडल अध्यक्ष कुलदीप सिंह त्यागी, जिलाध्यक्ष पं० मनु शर्मा एडवोकेट, जिलामहासचिव संजीव जिन्दल आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे ।

संक्षिप्त समाचार

दाखिल खारिज में गड़बड़ी, सीओ के निलंबन की 'रिकमेंडेशन'

लोकतंत्र की शान : हाजीपुर। वैशाली में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा शुरू किए गए 'सहयोग शिविर' के पहले ही दिन बड़ी कार्रवाई हुई है। तिरहुत प्रक्षेत्र के कमिश्नर गिरिवर दयाल ने ग़ोरौल अंचल के सीओ (अंचल अधिकारी) के निलंबन की अनुशंसा की है। यह कार्रवाई जमीन परिमार्जन और दाखिल खारिज (म्यूटेशन) में अनियमितताओं की शिकायतें मिलने के बाद की गई। कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि यह शिविर केवल शिकायतें लेने के लिए नहीं, बल्कि उनके तत्काल समाधान के लिए लगाए गए हैं। आयुक्त गिरिवर दयाल ने कहा कि यदि कहीं भी कोई शिकायत मिलती है, तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और लोगों की शिकायतों का तुरंत निपटारा किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरे बिहार में आज से 'सहयोग शिविर' की शुरुआत हुई है, जिसके तहत वैशाली जिले के सभी 18 प्रखंडों की पंचायतों में शिविर लगाए गए। इन शिविरों में बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। कमिश्नर ने बताया कि शिविर में कई गंभीर मामले और शिकायतें सामने आई हैं, जिनके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। ग़ोरौल प्रखंड के कटरमाला पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में तिरहुत रेंज के कमिश्नर गिरिवर दयाल और आईजी चंदन कुशवाहा मौजूद थे। उन्होंने लोगों की शिकायतें सुनीं और अधिकारियों को उनके शीघ्र निपटारे का आदेश दिया। शिविर के पहले ही दिन अधिकारियों की लापरवाही उजागर हुई, जिस पर तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देशों का अधिकारियों पर दिख रहा असर माना जा रहा है।

बस ने कंडक्टर को रौंदा, मौत, रामाशीष चौक पर हुआ एक्सीडेंट, 20 साल से कर रहा था काम

लोकतंत्र की शान : हाजीपुर। वैशाली में एक बस कंडक्टर की अपनी ही बस से कुचलकर मौत हो गई। यह घटना सोमवार शाम करीब 4 बजे सदर थाना क्षेत्र के रामाशीष चौक पर हुई। मृतक की पहचान लालगंज थाना क्षेत्र के एतबारपुर सिसौला निवासी विनोद राय (45) के रूप में हुई है। विनोद राय स्वर्गीय जगदीश राय के पुत्र थे। वह पिछले 20 वर्षों से 'रौशन बस' में कंडक्टर के पद पर कार्यरत थे। बताया जा रहा है कि जिस बस में वह ड्यूटी कर रहे थे, उसी बस की चपेट में आने से उनकी जान चली गई। विनोद राय अपने तीन भाइयों और दो बहनों में तीसरे नंबर पर थे। उनके परिवार में दो बेटे और एक बेटी है। इस दुखद घटना के बाद से पूरे परिवार में शोक का माहौल है। मृतक विनोद राय पूर्व RJD विधायक मुकेश कुमार रौशन की 'रौशन ट्रैवल्स' में काम करते थे। मृतक के भतीजे ने बताया कि उनके चाचा महुआ के पूर्व विधायक की बस में काम करते थे और रामाशीष चौक के पास सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। उन्होंने पुष्टि की कि जिस बस में चाचा ड्यूटी करते थे, उसी बस से यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों से उन्हें घटना की सूचना मिली। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।

फुलार घाट पर बुजुर्ग की डूबने से मौत, वैशाली में मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण भटका था

लोकतंत्र की शान " हाजीपुर। वैशाली थाना क्षेत्र के फुलार घाट पर रविवार शाम करीब 5 बजे एक वृद्ध व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर वैशाली थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। मृतक की पहचान वैशाली थाना क्षेत्र के धनवारी टोला गांव निवासी स्वर्गीय जुलम पासवान के 55 वर्षीय पुत्र गणेश पासवान के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक के बेटे पवन पासवान ने बताया कि उनके पिता का दिमागी संतुलन ठीक नहीं था, जिसके कारण वे कभी-कभी घर से भटक जाते थे। रविवार को भी वे घर से कब निकले, परिवार को इसकी जानकारी नहीं मिली। शाम करीब 5 बजे पुलिस से ही उनके डूबने से मौत होने की सूचना मिली। गणेश पासवान अपने पांच बहनों और एक भाई में सबसे छोटे थे। उनके परिवार में दो बेटे और एक बेटी हैं।

गैस सिलेंडर ब्लैकमार्केटिंग का खुलासा, पुलिस ने मैना गांव से 15 सिलेंडर और अवैध कार्ड जब्त किए

लोकतंत्र की शान : हाजीपुर। वैशाली में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने बेलसर थाना क्षेत्र के मैना गांव में छापेमारी कर भारी मात्रा में गैस सिलेंडर और अवैध गैस कार्ड बरामद किए हैं। एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की जांच में जुट गई है।यह मामला वैशाली जिले के बेलसर थाना क्षेत्र के मैना गांव का है, जहां घरेलू गैस सिलेंडरों की खुलेआम कालाबाजारी की जा रही थी। बताया जा रहा है कि गरीब और जरूरतमंद लोगों को मिलने वाले गैस सिलेंडरों को अवैध तरीके से ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा था। वैशाली एसपी विक्रम सिहाग को गुप्त सूचना मिली थी कि मैना गांव में गैस सिलेंडर 2100 रुपये से लेकर 5100 रुपये तक में बेचे जा रहे हैं। सूचना मिलते ही एसपी के निर्देश पर महुआ एसडीपीओ गोपाल मंडल के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ग्राहक बनकर मैना गांव निवासी लुट्टू चौधरी के घर पहुंची। टीम ने जब गैस सिलेंडर की मांग की, तो उन्हें अलग-अलग कीमतें बताई गईं। कालाबाजारी की पुष्टि होते ही टीम ने तुरंत घर में छापेमारी कर दी। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 6 भरे हुए और 9 खाली गैस सिलेंडर बरामद किए। इसके अतिरिक्त, भारी मात्रा में अवैध गैस कार्ड भी जब्त किए गए हैं। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस ने बेलसर प्रखंड के अंचल अधिकारी और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को सूचित किया। इसके बाद, जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। आशंका जताई जा रही है कि यह मामला केवल एक घर तक सीमित नहीं है, बल्कि गैस सिलेंडर की कालाबाजारी का एक बड़ा नेटवर्क इलाके में सक्रिय हो सकता है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इतने बड़े पैमाने पर गैस सिलेंडर और गैस कार्ड कहां से लाए जा रहे थे और इस रैकेट में कौन-कौन लोग शामिल हैं। पुलिस और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से इस पूरे मामले की गहन जांच कर रहे हैं।

मुजफ्फरपुर में तीन हजार लीटर विदेशी शराब जब्त

लोकतंत्र की शान : मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की है। राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो से मिली गुप्त सूचना के आधार पर हथौड़ी थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 3389.4 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई। इस दौरान तस्करी में इस्तेमाल हो रही पांच गाड़ियां भी बरामद की गई। हालांकि, तस्कर मौके से फरार हो गए। यह कार्रवाई बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के प्रयासों का हिस्सा है। पटना स्थित राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को मुजफ्फरपुर के हथौड़ी थाना क्षेत्र में विदेशी शराब की एक बड़ी खेप उतारे जाने की सटीक जानकारी मिली थी। इस महत्वपूर्ण इनपुट को तुरंत मुजफ्फरपुर के एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा के साथ साझा किया गया। सूचना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने तत्काल एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया और छापेमारी के निर्देश दिए। एसएसपी की ओर से गठित विशेष टीम ने हथौड़ी थाना अंतर्गत भदई गाछी इलाके में घेराबंदी शुरू की। पुलिस को देखते ही शराब अनलोड कर रहे तस्करों में हड़कंप मच गया। वे मौके पर ही वाहन और शराब छोड़कर भागने लगे। पुलिस ने पीछा किया, लेकिन घने जंगल और झाड़ियों का फायदा उठाकर सभी आरोपी फरार हो गए। पुलिस अब फरार आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। जिसका उपयोग शराब की मुख्य खेप को एक राज्य या जिले से दूसरे स्थान तक लाने के लिए किया गया था। इस बेहद महंगी और लग्जरी गाड़ी का इस्तेमाल रेकी करने या सुरक्षित परिवहन के लिए हो रहा था। जो मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी इलाके की एक फर्नीचर दुकान से जुड़ी बताई जा रही है। जिन पर भारी मात्रा में शराब के कार्टन लदे हुए थे। एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि शराब तस्कर पुलिस की नजरों से बचने के लिए बेहद शातिराना तरीका अपना रहे थे। वे शराब की तस्करी के लिए वीआईपी नंबर प्लेट वाली महंगी और लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि सड़कों पर चेकिंग के दौरान किसी को शक न हो।

थोक व खुदरा दवा दुकानें आज रहेंगी बंद, औषधि केंद्र खुले रहेंगे

एजेंसी, पटना

देशभर में 20 मई को प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी केमिस्ट हड़ताल के बीच प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (PMBJK) रिटेलर एसोसिएशन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। एसोसिएशन ने घोषणा की है कि देशभर के जन औषधि केंद्र इस हड़ताल में शामिल नहीं होंगे। सामान्य दिनों की तरह खुले रहेंगे। यह फैसला आम मरीजों को सस्ती दवाइयों की उपलब्धता कराने के उद्देश्य से लिया गया है। एसोसिएशन के महासचिव सुरेश मित्तल ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि यह निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत सिंह के साथ विस्तृत चर्चा के बाद लिया गया है। संगठन का मानना है कि जन औषधि केंद्र गरीब, मध्यम वर्ग और जरूरतमंद मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं और इन्हें बंद करना जनहित के खिलाफ होगा।

औषधि केंद्र बंद होने से मरीजों को परेशानी होगी: एसोसिएशन ने तर्क दिया कि यदि जन औषधि केंद्र भी बंद होते हैं, तो लाखों मरीजों को आवश्यक दवाइयों के लिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से बुजुर्ग, गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीज और आर्थिक रूप से कमजोर लोग इससे सबसे अधिक प्रभावित होंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए, सभी रिटेलरों से अपने-अपने केंद्र नियमित रूप से संचालित करने की अपील की गई है। संगठन ने भरोसा दिलाया है कि हड़ताल के दिन भी मरीजों को आवश्यक दवाइयों और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता दी जाएगी। जन औषधि केंद्रों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराना है और इस उद्देश्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

❑ सस्ती कीमत पर मिलती रहेंगी दवाइयां

पटना के बड़े सरकारी अस्पताल में सक्रिय रहेंगे केंद्र: एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि पटना सहित बिहार के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता बनाए रखने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। राजधानी पटना के IGIMS, AIIMS, PMCH, NMCH, LNJP और गार्डिनर अस्पतालों के आसपास स्थित जन औषधि केंद्रों को विशेष रूप से सक्रिय रहने का निर्देश दिया गया है, ताकि मरीजों और उनके परिजनों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। संगठन ने कहा कि अस्पतालों में प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं।

ऐसे में यदि दवा दुकानों पर असर पड़ता है तो मरीजों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसी कारण जन औषधि केंद्रों को निर्बाध रूप से संचालित करने की तैयारी की गई है। दवाइयों की कमी नहीं होने दी जाएगी एसोसिएशन की बैठक में कोषाध्यक्ष सुनील कुमार, कर्नाटक से सदस्य अशोक कुमार और ओडिशा से सदस्य पीके सिन्हा भी मौजूद रहे। सभी पदाधिकारियों ने एकमत होकर कहा कि संगठन की प्राथमिकता जनता की सुविधा और स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतरता बनाए रखना है।

पीयू के इकबाल हॉस्टल से 2 सुतली बम बरामद

एजेंसी, पटना

पटना यूनिवर्सिटी के इकबाल हॉस्टल से 2 जिंदा सुतली बम बरामद किए गए हैं। पीरबहोर थाने की पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हॉस्टल के छात्र आपसी रंजिश में बमबाजी की घटना को अंजाम देने की तैयारी में हैं। दो गुटों की लड़ाई के बीच कभी भी बमबाजी की जा सकती है। इसी सूचना के आधार पर इकबाल हॉस्टल की तलाशी ली गई। जहां हॉस्टल के पीछे खंडहरनुमा भवन से 2 जिंदा सुतली बम मिले। दोनों बम प्लास्टिक में लपेटकर रखे गए थे। फिलहाल पटना यूनिवर्सिटी के सभी हॉस्टल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देर रात तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद थे। पुलिस ने समय रहते कैंपस के अंदर हिंसक झड़प को टाल दिया है।

एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई कर रही पुलिस: टाउन डीएसपी 1 राजेश रंजन के नेतृत्व में इकबाल, जैक्सन, नदवी, कैंडविश, Minto हॉस्टल में रात 2:00 तक सर्च किया गया है। हालांकि इस दौरान 2 सुतली बम के अलावा अन्य कुछ बरामद नहीं हुआ। फिलहाल पुलिस की ओर से बम स्क्वॉड की टीम को डिफ्यूज के लिए यूनिवर्सिटी के कैंपस में बुलाया गया है। डिफ्यूज करने के बाद एफएसएल में भेजा जाएगा। दूसरी तरफ अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज करके पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। टाउन डीएसपी 1 राजेश रंजन ने बताया कि बम डिटेक्शन और डिस्पोजल टीम बुलाई गई थी। खंडहरनुमा भवन से 2 जिंदा सुतली बम मिले हैं। इस तरह की आपराधिक गतिविधि में लगे शरारती तत्वों के बारे में पता लगाया जा रहा है। फिलहाल अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

♦ रात 2 बजे तक चला सर्च ऑपरेशन, छात्र आपसी रंजिश में बमबाजी करने वाले थे

एमपी में बैंक लूटने वाले 3 बदमाश पटना में धराए

लोकतंत्र की शान , पटना

मध्य प्रदेश के सिंगरौली के बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बैढ़न शाखा से तकरीबन 15 करोड़ के गहने और कैश लूटे गए थे। मामले में पटना से 3 बदमाश पकड़े गए हैं। टाउन डीएसपी-1 राजेश रंजन ने बताया कल मध्य प्रदेश की पुलिस आई थी। मध्य प्रदेश पुलिस, पटना पुलिस और एसटीएफ के सहयोग से कुमकुम सिंह लेन से हर्ष (संडलपुर), प्रभाकर (सुल्तानगंज) और रवि नन्दन कुमार (सुल्तानगंज) को अरेस्ट किया गया है। तीनों पटना के रहने वाले हैं। हाल में अपना ठिकाना परसा बाजार बनाया था। प्रभाकर की गिरफ्तारी पीरबहोर इलाके से हुई से हुई है। इनके बारे में और पता लगाया जा रहा है। इनके ऊपर मध्य प्रदेश के सिंगरौली में 9 केजी सोना और 20 लाख रुपए बैंक से लूटने के आरोप हैं।

❑ 15 करोड़ के गहने और कैश लूट ले गए थे, मध्य प्रदेश की पुलिस बिहार आई थी

17 अप्रैल को की थी वारदात: 17 अप्रैल को दोपहर करीब 12:50 बजे बैढ़न स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा में 5 बदमाशों ने धावा बोलकर लगभग 15 करोड़ रुपए की लूट की थी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे।

सहयोग शिविरों का निरीक्षण करने पहुंचे शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव, पतरघट में 122 में से 120 आवेदनों का हुआ निष्पादन

लोकतंत्र की शान

सहरसा, मो. जियाउद्दीन, जिला संवाददाता, सहरसा। जिले में चल रहे पंचायत स्तरीय "सहयोग शिविर" की निगरानी के क्रम में मंगलवार को शिक्षा विभाग के सचिव सह प्रभारी सचिव श्री विनोद सिंह गुंजियाल ने विभिन्न प्रखंडों का दौरा कर शिविरों का निरीक्षण किया। उन्होंने पतरघट प्रखंड के बिशुनपुर पंचायत सरकार भवन, बनमा ईटहरी प्रखंड के पैक्स गोदाम परिसर तथा सोनवर्षा प्रखंड के मंगवार पंचायत सरकार भवन में आयोजित सहयोग शिविर में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया और आम जनता की सुविधा के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रभारी सचिव ने शिविर में प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की स्थिति की भी विस्तृत जानकारी ली। अधिकारियों से बातचीत के दौरान उन्होंने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि सभी शिकायतों का समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से निवारण किया जाए, ताकि आम लोगों को त्वरित राहत मिल सके। प्राप्त जानकारी के अनुसार पतरघट प्रखंड में कुल 122 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 120 आवेदनों का निष्पादन मौके पर ही कर दिया गया है। शेष आवेदनों के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई जारी है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सहयोग शिविर के माध्यम से लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए और सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र लोगों तक पहुंचाया जाए।

सहरसा में 15 स्थलों पर लगा 'सहयोग शिविर', 85% आवेदनों का हुआ निष्पादन, ग्रामीणों ने सराहा पहल

लोकतंत्र की शान

सहरसा, मो. जियाउद्दीन, जिला संवाददाता: सहरसा। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मंगलवार को सहरसा जिले के विभिन्न प्रखंडों में कुल 15 स्थलों पर जिलाधिकारी, उप विकास आयुक्त, नगर आयुक्त, अपर समाहर्ता एवं अन्य वरीय पदाधिकारियों के नेतृत्व में पंचायत स्तरीय "सहयोग शिविर" का आयोजन किया गया। इस शिविर के माध्यम से बड़ी संख्या में आए आवेदकों एवं लाभुकों को आवेदन निष्पादन तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित प्रमाण पत्र मौके पर ही प्रदान किए गए। कहरा प्रखंड के बेल्हापट्टी पंचायत में आयोजित शिविर का शुभारंभ शिक्षा मंत्री सह प्रभारी मंत्री श्री मिथिलेश तिवारी, जिलाधिकारी श्री दीपेश कुमार एवं पुलिस अधीक्षक श्री हिमांशु द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर स्थानीय ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों, महिला समूहों की सदस्याओं तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। अपने संबोधन में प्रभारी मंत्री श्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि सहयोग शिविर का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं एवं जनहित से जुड़े कार्यों से संबंधित शिकायतों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार योजनाओं के पारदर्शी एवं सुचारु क्रियान्वयन तथा जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रतिबद्ध है, और इसी लक्ष्य के तहत पंचायत स्तर पर इस प्रकार के शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी श्री दीपेश कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा प्राप्त आवेदनों के निवारण हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयासों के परिणामस्वरूप लगभग 85 प्रतिशत आवेदनों का निष्पादन निर्धारित समय सीमा से पूर्व ही कर लिया गया है, जबकि शेष लंबित आवेदनों के समाधान के लिए कार्रवाई प्रगति पर है और उन्हें 30 दिनों के भीतर निष्पादित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान प्रभारी मंत्री, जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा कुल 57 लाभुकों—जिनमें श्री रामचंद्र यादव, श्री साजन राम, सुश्री सरस्वती कुमारी, श्री आदर्श कुमार, श्री सत्यनारायण भगत, श्री राजेश्वर यादव, सुश्री आंचल कुमारी सहित अन्य—को योजना लाभ एवं आवेदन निष्पादन से संबंधित प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

21 मई को शहर का कचरा नहीं उठाएंगे सफाईकर्मी

स्वच्छता सर्वेक्षण में गिर सकती सिटी की रैंकिंग

लोकतंत्र की शान , पटना

पटना में अभी स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है। इस बीच शहर में कचरे का अंबार लगने वाला है। 21 मई को पटना नगर निगम के 8000 कर्मी एक दिवसीय हड़ताल पर जाएंगे। इसमें मजदूर, सफाई कर्मी, ड्राइवर, स्वीपर शामिल हैं। पटना नगर निगम कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के प्रवक्ता जितेंद्र कुमार ने कहा कि हड़ताल को लेकर आयोजित बैठक में इस बात पर रोष व्यक्त किया गया कि तात्कालीन नगर आयुक्त के जाते ही नगर निगम कर्मचारियों का वेतन, पेंशन समय पर नहीं मिल पा रहा है। कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के बकाया का भुगतान नहीं हुआ है।

जुलाई में होगा अनिश्चितकालीन हड़ताल: सफाई कर्मियों ने चेतावनी दी है कि अगर मांगें पूरी नहीं हुई तो जुलाई में अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी।

♦ पटना में 8000 जाएंगे हड़ताल पर

वेतन भुगतान को लेकर विभिन्न स्तरों पर अनावश्यक विलंब, टालमटोल और उपेक्षापूर्ण प्रशासनिक रवैया अपनाया जा रहा है। हड़ताल में सड़क पर कचरा फैल जाएगा। दुर्गन्ध के चलते सड़कों पर चलना मुश्किल हो जाएगा। बारिश का भी सीजन आने वाला है। ऐसे में शहर के गली-मोहल्ले और मुख्य सड़कों पर कूड़ा-कचरा सड़ने लगेगा।

45° डिग्री के करीब पहुंचा 3 जिलों का तापमान

एजेंसी, पटना

कुछ दिनों की राहत के बाद पटना सहित पूरे राज्य में एक बार फिर गर्मी बढ़ गई है। सोमवार को प्रदेश के 3 जिलों का तापमान 45°C के करीब पहुंच गया, जो इस साल बिहार में मौसम का सबसे गर्म दिन रहा। 44.6°C के साथ गयाजी सबसे गर्म जिला रहा। रोहतास का तापमान 44.5°C , जबकि बक्सर का तापमान 44.4°C दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने आज रोहतास, कैमूर और बक्सर में हीटवेव का रेड अलर्ट जारी किया है। भीषण गर्मी को देखते हुए बक्सर डीएम ने क्लास 1 से 8 तक के सभी निजी और सरकारी स्कूल 31 मई तक के लिए बंद करने का आदेश दिया है। वहीं समस्तीपुर में सुबह 11 बजे तक ही क्लास चलेंगे। मौसम विभाग के अनुसार अगले चार दिनों तक तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। दिन में तेज धूप और उमस लोगों को परेशान करेगी। शाम के समय कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं, बिहार में 25 मई से नौतपा की शुरुआत हो रही है, जो 2 जून तक रहेगा। इस दौरान लगातार 9 दिनों तक भीषण गर्मी और लू का असर देखने को मिलेगा। इस अवधि में तापमान अपने चरम पर पहुंच सकता है।

दानापुर में पंचायत स्तर पर 'सहयोग शिविर'

लोकतंत्र की शान , पटना

बिहार सरकार ने आम लोगों की समस्या के समाधान के लिए पंचायत स्तर पर पहल की जा रही है। पटना जिला प्रशासन की ओर से दानापुर प्रखंड में 'सहयोग शिविर' की शुरुआत हुई है, जिसका उद्घाटन उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने किया। यह शिविर दानापुर प्रखंड की सरारी पंचायत के दरियापुर गांव में लगा है। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से की गई है। मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को उनकी छोटी-बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए प्रखंड और जिला मुख्यालय के चक्कर लगाने से राहत दिलाना है। शिविर में पहुंची रिंकू देवी ने कहा कि मेरी जमीन का जबरन कब्जा किया जा रहा है। 7 मई की रात को बाउंड्री तोड़ दी गई। केस हुआ, पर कार्रवाई नहीं हुई है। शिकायत लेकर शिविर में आई हूं। यहां करना है बताया ही नहीं जा रहा है।

लापरवाही करने वाले अधिकारी पर कार्रवाई होगी: डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने कहा कि ये बहुत ही जनउपयोगी कार्यक्रम है। जिन लोगों ने जिस विभाग की शिकायतें पहले की थी, उन सब की जांच कर निदान कर दिया गया है। आज भी अलग-अलग विभाग के स्टॉल बने हैं। जितने भी आवेदन आएंगे। सब को ऑनलाइन भी रखा जाएगा। समय पर 30 दिन के अंदर निष्पादन होगा। जो अधिकारी लापरवाही करेंगे उनपर कार्रवाई होगी।

❑ डिप्टी सीएम ने किया उद्घाटन, समस्या लेकर पहुंची महिला बोली, क्या करना है बताया ही नहीं जा रहा

आवास योजना घर की चाबी सौंपी: लाभार्थी रीमा कुमारी ठाकुर, हेमंती देवी को लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार का चेक दिया गया है। लाभार्थी सुषमा देवी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर की चाबी दी गई। लाभार्थी रूबी देवी को लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तरह 1100 का चेक दिया गया। लाभार्थी सिम्मी देवी को राशन कार्ड का लाभ दिया गया। इसके साथ ही एक अन्य महिला को भूबंदोबस्ती का लाभ दिया गया।

शिविर में राजस्व, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, मनरेगा, बिजली, जलापूर्ति, सड़क, आपूर्ति और पंचायत विभाग सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद हैं। ग्रामीण अपनी व्यक्तिगत और सार्वजनिक समस्याओं से जुड़े आवेदन सीधे इन अधिकारियों को सौंप सकेंगे। प्रशासन का लक्ष्य है कि प्राप्त शिकायतों का निष्पादन 30 दिनों अंदर किया जाए। कई मामलों का मौके पर ही समाधान करने का भी प्रयास किया जाएगा।

संक्षिप्त समाचार

मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

लखनऊ : मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक मंगलवार को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में हुई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की। बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मेजबान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी मौजूद रहे। बैठक के उपरांत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर पोस्ट किया। मुख्यमंत्री ने लिखा कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में सहभाग किया। बैठक में जनकल्याण, सुशासन, क्षेत्रीय विकास, कुपोषण उन्मूलन, स्कूल ड्रॉपआउट में कमी लाने, यौन अपराधों में शत-प्रतिशत दोषसिद्धि सुनिश्चित करने एवं राज्य-स्तरीय साइबर हेल्पलाइन जैसे अहम विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने लिखा कि सहकारी संघवाद, समन्वित विकास और राज्यों के मध्य बेहतर तालमेल को नई दिशा देने वाला यह मंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 'विकसित भारत' के सामूहिक संकल्प को और अधिक सशक्त करेगा।

ईओ ने ली प्रगणक एवं सुपरवाइजरों की मीटिंग

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा, हसनपुर/उझारीः मंगलवार को जनगणना संबंधित चार्ज अधिकारी नगर पंचायत उझारी ने जनगणना प्रगणकों एवं सुपरवाइजरों की मीटिंग ली एवं सभी को जनगणना से संबंधित किटो एवं अन्य सामग्री का वितरण किया गया। तथा स्वयं गणना के लिए जागरूक किया गया, बताते चलें कि मंगलवार को नगर पंचायत कार्यालय के सभागार कक्ष में अधिशासी अधिकारी एवं जनगणना चार्ज अधिकारी विजयपाल सिंह ने प्रगणकों एवं सुपरवाइजरों की एक मीटिंग लेकर उन्हें अपने दायित्व के बारे में समझाया। उन्होंने कहा कि लोगों को स्वयं गणना के बारे में जागरूक किया जाए। मीटिंग में कीट एवं सामग्री का वितरण किया गया। जनगणना में 47 प्रगणक एवं 8 सुपरवाइजर लगाए गए हैं। वही अधिशासी अधिकारी विजयपाल सिंह ने नागरिकों से जनगणना में सहयोग करने की भी अपील की है, तथा मीटिंग में मुख्य रूप से अधिशासी अधिकारी विजयपाल सिंह, लिपिक नवीन कुमार अग्रवाल, लिपिक कृष्ण दत शर्मा, मोहम्मद यामीन, निजामुद्दीन, मोहम्मद जुहैब, बचन सिंह आदि सहित प्रगणक व सुपरवाइजर उपस्थित रहे।

इनर व्हील क्लब ऑफ़ हसनपुर ने विद्यालय में कराई पोस्टर प्रतियोगिता

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा, हसनपुरः मंगलवार को नगर के शिवाला मंदिर के सामने स्थित रामचरण दास पुरुषोत्तम शरण बालिका इंटर कॉलेज में हसनपुर नगर की समाजसेवी संस्था इनर व्हील क्लब ऑफ हसनपुर के द्वारा विद्यालय की छात्राओं के बीच एक पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसका विषय अंगदान रहा, प्रतियोगिता में दर्जनों छात्राओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और एक से बढ़कर एक पोस्टर बनाएं वही पोस्टर प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा अन्य सभी छात्राओं को सांत्वना पुरस्कार दिया गया, साथ ही क्लब के द्वारा विद्यालय को एक छत का पंखा भी प्रदान किया गया, बताते चलें कि इनर व्हील क्लब ऑफ हसनपुर द्वारा नगर मे समाज सेवा के कार्य आए दिन किए जाते रहते हैं, इस मौके पर इनर व्हील क्लब ऑफ़ हसनपुर की अध्यक्षा आरती गुप्ता, सचिव सोनिया रस्तोगी, कविता अग्रवाल, अंचल अग्रवाल, प्रियंका गर्ग तथा विद्यालय की प्रधानाचार्य अंकिता शर्मा सहित विद्यालय का समस्त स्टाफ एवं छात्राएं मौजूद रही l

लिंगानुपात गिरावट रोकने में असफल चार अधिकारी निलंबित

लोकतंत्र की शान : चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने गिरते लिंग अनुपात और पीसी-पीएनडीटी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने पर तीन वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों (एसएमओ) तथा एक चिकित्सा अधिकारी (एमओ) को निलंबित कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा के अनुसार सोनीपत, यमुनानगर, रोहतक तथा नारनौल जिलों में तैनात डॉ. टीना आनंद, डॉ. विजय परमार, डॉ. सतपाल, डॉ. प्रभा ने लिंग अनुपात सुधार के लिए चलाए जा रहे अभियानों की प्रभावी निगरानी नहीं की। इन अधिकारियों ने कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए बनाए गए तंत्र को सख्ती से लागू नहीं किया। इसके अलावा, संबंधित जिलों में पीसी-पीएनडीटी एक्ट के तहत आवश्यक कार्रवाई और फॉलोअप में गंभीर लापरवाही बरती। अधिकारियों और फील्ड टीमों के बीच समन्वय सुनिश्चित नहीं किया। इन गंभीर आरोपों के बाद चार अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस कार्रवाई के जरिए सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि लिंग अनुपात सुधार में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिम्मेदार अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाएगी। दोषी पाए जाने पर कड़ी विभागीय कार्रवाई जारी रहेगी। सरकार का मानना है कि यदि जिम्मेदार अधिकारी अपने दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन नहीं करेंगे, तो कन्या भ्रूण हत्या पर प्रभावी रोक लगाना संभव नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि हरियाणा कभी देश के सबसे खराब लिंग अनुपात वाले राज्यों में शामिल रहा है। पिछले वर्षों में सरकार के लगातार प्रयासों से इसमें उल्लेखनीय सुधार हुआ है। निलंबन अवधि के दौरान इन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की जाएगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई तय की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के इस फैसले को राज्य में पीसी-पीएनडीटी कानून के सख्त अनुपालन और लिंग अनुपात सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

ऑपरेशन प्रहार 2.0 के तहत थाना कमर्जी पुलिस की बड़ी कार्यवाही

» विंध्य क्षेत्र में सक्रिय अवैध नशीले कफ सिरप तस्करी गिरोह का पर्दाफाश

» 11,88,918 रुपये का मशरूका जप्त

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

सीधी। पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन गौरव राजपूत द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार 2.0 के अंतर्गत नशे के विरुद्ध विशेष अभियान के तहत उप पुलिस महानिरीक्षक रीवा क्षेत्र हेमंत चौहान के मार्गदर्शन, पुलिस अधीक्षक सीधी संतोष कोरी के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव एवं एसडीओपी चुरहट रवि प्रकाश कौल के नेतृत्व में थाना कमर्जी पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध बड़ी एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुए विंध्य क्षेत्र में सक्रिय नशीले कफ सिरप तस्करी गिरोह का खुलासा किया गया। कार्यवाही के दौरान भारी मात्रा में अवैध आनरेक्स कफ सिरप एवं परिवहन में प्रयुक्त वाहन सहित कुल 11,88,918 रुपये का मशरूका जप्त किया गया। पुलिस के अनुसार 18 मई 2026 को थाना कमर्जी पुलिस टीम द्वारा ग्राम बरिगवां क्षेत्र में जुर्म जरायम पतासाजी एवं अवैध मादक पदार्थ संबंधी सूचना की तस्दीक की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक सफेद रंग की बोलेरो वाहन क्रमांक एमपी 53 जेडडी 2859 जिसमें जय बाबा नीम करौरी महाराज, माता-पिता का आशीर्वाद लिखा हुआ है में भारी मात्रा में अवैध नशीला कफ सिरप लोड कर सीधी की ओर ले जाया जा रहा है। साथ ही एक सफेद रंग की टाटा कर्व वाहन क्रमांक एमपी 53 जेडएफ 7457 भी संदिग्ध रूप से साथ चल रही है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा पंचगणों की उपस्थिति में मुखबिर सूचना पंचनामा तैयार कर अमल्लकपुर- कोलघाट

मार्ग पर घेराबंदी की गई। घेराबंदी के दौरान कोलघाट रोड स्थित पहाड़ी क्षेत्र में संदिग्ध बोलेरो वाहन लावारिस अवस्था में खड़ा मिला। वाहन की तलाशी वीडियोग्राफी एवं पंचगणों की उपस्थिति में ली गई, जिसमें कुल 5 सफेद बोरियों में रखे कार्टूनों से 912 शीशी ऑनरेक्स कफ सिरप बरामद किया गया। प्रत्येक शीशी 100 एमएल की थी, जिसमें कोडीन फास्फेट पाया गया। प्राप्त मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत 1,83,768 रुपये तथा परिवहन में प्रयुक्त बोलेरो वाहन की कीमत लगभग 10 लाख रुपये आंकी गई है। वाहन से आरोपी प्रीतम पटेल उर्फ सनी निवासी चिलरी खुर्द थाना कमर्जी के दस्तावेज, बैंक कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एवं नगदी राशि 5,150 रुपये भी बरामद किए गए। विवेचना में सामने आए तथ्य प्रारंभिक विवेचना एवं मुखबिर सूचना से यह तथ्य सामने आया कि आरोपी प्रीतम पटेल उर्फ सनी एवं अनिल पटेल उर्फ डीजे वाला निवासी दादर पोस्ट लकोड़ा थाना कमर्जी, रीवा क्षेत्र से अवैध मादक पदार्थ लाकर विंध्य क्षेत्र में तस्करी करते थे। दोनों आरोपी अवैध ड्रग कारोबार को आर्थिक सहायता उपलब्ध करानेए मादक पदार्थों की तस्करी करने एवं अपराधियों को संरक्षण देने में संलिप्त पाए गए हैं। टनल मोहनिया के सीसीटीवी फुटेज से भी आरोपियों की गतिविधियों की पुष्टि हुई है। पुलिस दबिश की आशंका पर आरोपी वाहन छोड़क़र फरार हो गए। आरोपियों की तलाश हेतु संभावित स्थानों पर लगातार दबिश दी जा रही है तथा अन्य तकनीकी साक्ष्य एकत्रित कर विश्लेषण किया जा रहा है। आरोपीगण के विरुद्ध थाना कमर्जी में धारा 8, 21, 22, 27-ए एनडीपीएस एक्ट एवं 5/13 ड्रग्स कंट्रोल एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कमर्जी उप निरीक्षक इन्द्राज सिंह, प्रआर अभय वर्मा, आरक्षक मुकेश रावत, आरक्षक 139 दीपक सिंह, आरक्षक 460 शिवम पाण्डेय एवं आरक्षक सोनू यादव का सराहनीय योगदान रहा।

नकली संगठन बनाकर जन स्वास्थ्य कर्मचारी से ना करें खिलवाड़, आरके नागर

लोकतंत्र की शान, राजेन्द्र करनाल की रिपोर्ट

सोनीपत : जन स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन नंबर 1266 हेड ऑफिस सोनीपत प्रेस बयान जारी करते हुए कहा है कि, हमारी असली यूनियन ने नकली हुड़ा जन स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन नंबर 1266 मुख्यालय पंचकूला और हेड क्वार्टर गुड़गांव और जींद लिखने वाले नकली व फर्जी तथा असंवैधानिक राज्य कमेटी तथा सोनीपत सहित अन्य जिलों की चुनाव कमेटियों को रद्द करते हुए उनके विरुद्ध मुख्य प्रशासक एचएसवीपी पंचकूला को तथा लेबर कमिश्नर हरियाणा चंडीगढ़ को अपना पत्र नंबर 271 से 320 दिनांक 18- 5 -26 डायरी करा कर रिसीव कर दिया है। ओर इन लोगों के साथ वार्ता करने तथा इनके पत्रों पर अमल न करने तथा इनके रजिस्ट्रेशन नंबर की जांच करने की मांग की गई है। जिसके पास हुड्डा जन स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन नंबर 1266 का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वही अधिकारियों व सरकार से वार्ता करेगा। और पत्र व्यवहार करेगा। असंवैधानिक और नकली व फर्जी पदाधिकारीयों पर बैन लगाने की मांग की गई है। इस यूनियन का रजिस्ट्रेशन नंबर 1266 आर.के . नागर सोनीपत के नाम से जारी किया हुआ है। इसकी प्रतिया सभी पत्रकारों और अधिकारियों को पहले कई बार भेजी जा चुके हैं ।और आज भी संलग्न हैं।

भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन शिखर पैलेस वेन्यू में कार्यक्रम संपन्न प्रमाण पत्र बांटे गए

लोकतंत्र कि शान हसनरसीद जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर कटनी मध्य प्रदेश

जबलपुर : भारतीय मानव अधिकार एसोसिएशन जो एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है पूरे हिंदुस्तान में यह अपना समाज के अंदर जो बुराइयां हैं उसकी लड़ाई लड़ने के लिए समाज को न्याय दिलाने के लिए संगठन पूरे हिंदुस्तान में मानव सेवा का काम कर रहा है जो विगत दिनों जबलपुर के शिखर पैलेस वेन्यू में मानव अधिकार संगठन के द्वारा एक विधिवत कार्यक्रम के माध्यम नए सदस्यों को जोड़ने की प्रक्रिया किया गया इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग चंद्रवंशी और विशिष्ट अतिथि शर्मा जी का स्वागत मानव अधिकार के जिला अध्यक्ष राजेश कुमार मिश्रा और उनके टीम के गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया । इसके अतिरिक्त मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि के के द्वारा प्रमाण पत्र एवं कार्ड का वितरण किया गया इस कार्यक्रम में भारतीय मानवाधिकार संगठन के संभागीय अध्यक्ष राजेश कुमार तिवारी ने इससेपूर्व में मुख्य अतिथि मानव अधिकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग चंद्रवंशी जी, एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शर्मा जी एवं राष्ट्रीय महिला कार्यकारिणी श्रीमती चंद्रकला विश्वकर्मा मैडम को पुष्पा माला एवं गुलदस्ते से स्वागत किया गया सम्मान पूर्व प्रमाण पत्र भी दिए इसके अलावा जबलपुर केआसपास से पदाधिकारी एवं मे मेंबर्स को भी सम्मान पूर्व प्रमाण पत्र और कार्ड वितरण किया गया इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग चंद्रवंशी जी, एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शर्मा जी एवं राष्ट्रीय महिला कार्यकारिणी श्रीमती चंद्रकला विश्वकर्मा मैडम उपस्थिति रही मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग चंद्रवंशी और विशिष्ट अतिथि शर्मा जी के द्वारा समाज के प्रति विचार व्यक्त किए गए और भारतीय मानव अधिकार संगठन को मजबूत करने के और समाज को जोड़ने के लिए अपने उद्बोधन दिए अंत में मानव अधिकार के संभागीय अध्यक्ष राजेश कुमार तिवारीके द्वारा आभार व्यक्त किया।

चौपालों के माध्यम से जागरूकता लाने का प्रयास कर रही ढीमरखेडा पुलिस

लोकतंत्र ि शान हसन रशीद हसन रसीद जबलपुर कटनी मध्य प्रदेश

कटनी पुलिस अधीक्षक , अभिनय विश्वकर्मा के नेतृत्व में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कटनी डा संतोष डेहरिया के मार्गदर्शन तथा श्रीमती आकाँक्षा चतुर्वेदी एसडीओपी, स्लीमनाबाद के पर्यवेक्षण में थाना ढीमरखेड़ा द्वारा थाना क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न ग्रामों में ग्राम चौपालों के माध्यम से व्यापक जन-जागरूकता एवं जनसम्पर्क अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों के साथ सीधा संवाद स्थापित कर कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करना, अपराधों की रोकथाम हेतु जागरूकता बढ़ाना तथा पुलिस एवं आमजन के मध्य विश्वास को मजबूत करना है। थाना प्रभारी ढीमरखेड़ा अभिषेक चौबे एवं पुलिस स्टाफ द्वारा ग्राम पंचायत भवनों एवं सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित चौपालों में ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया तथा त्वरित निराकरण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। प्रमुख रूप से अभी तक कोठी, इटौली, बांध, ढीमरखेडा, सनकुई, मुरवारी, सिलाई, देवरी मारवाड़ी, पौड़ीखुर्द, सिमरिया, खमतरा, गूड़ा गांव में ग्राम चौपाल का आयोजन किया जा चुका है।

अभियान के अंतर्गत निम्न विषयों पर विशेष जागरूकता दी गई—

साइबर अपराध से बचावः ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, ओटीपी साझा न करने संबंधी सावधानियां एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी।

महिला एवं बाल सुरक्षाः घरेलू हिंसा, बाल विवाह, पॉक्सो अधिनियम तथा हेल्पलाइन 1090/1098 के संबंध में जानकारी।

नशामुक्ति अभियानः अवैध शराब एवं मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव बताते हुए ग्रामीणों को सूचना देने हेतु प्रेरित किया गया।

यातायात जागरूकताः हेलमेट एवं सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग तथा नाबालिगों द्वारा वाहन न चलाने की समझाइश।

अफवाहों से सावधानः सोशल मीडिया पर अपुष्ट खबरें साझा न करने एवं शांति बनाए रखने की अपील।

ग्राम चौपाल के दौरान ग्रामीणों को "डायल 112" आपातकालीन सेवा की जानकारी दी गई तथा संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को देने का आग्रह किया गया। साथ ही "पुलिस मित्र" बनकर सामुदायिक पुलिसिंग को मजबूत करने हेतु भी प्रेरित किया गया। थाना ढीमरखेड़ा पुलिस द्वारा यह संदेश दिया गया कि पुलिस और जनता के पारस्परिक सहयोग से ही सुरक्षित एवं अपराध मुक्त समाज की स्थापना संभव है। यह जन-जागरूकता अभियान निरंतर जारी रहेगा।

पंकज सिंह बने प्रदेश महामंत्री, जताया आभार

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

सीधी। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देशानुसार संगठन प्रभारी महासचिव डॉ. संजय कामले की सहमति से प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह परिहार द्वारा तेंदूपत्ता लघु वनोपज प्रकोष्ठ के प्रदेश पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। अनुमोदन उपरांत तेंदूपत्ता लघु वनोपज प्रकोष्ठ में उपाध्यक्ष, महासचिव एवं सचिव की नियुक्ति की घोषणा कर दी गई है। उक्त नियुक्ति में सीधी जिले के वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं लघु वनोपज संघ के जिलाध्यक्ष पंकज सिंह चौहान डैनिहा को प्रदेश महामंत्री पद से नवाजा गया है। बता दें कि पंकज सिंह चौहान लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं।

तेंदूपत्ता लघु वनोपज प्रकोष्ठ का प्रदेश महामंत्री बनाए जाने पर पंकज सिंह चौहान ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल,संगठन प्रभारी डॉ. संजय कामले एवं प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह परिहार सहित पार्टी के शीर्ष नेताओं के प्रति आभार व्यक्त किया है। वहीं श्री सिंह के प्रदेश महामंत्री बनाए जाने पर जिले के कांग्रेस नेताओं सहित उनके शुभचिंतकों ने हर्ष व्यक्त करते हुए बधाई दी है।

नकवेल में नहीं थम रहा बेखौफ अवैध उत्खनन का कारोबार

» सरकार को लाखों रुपए की हो रही क्षति,

» जिम्मेदारों की भूमिका कार्रवाई को लेकर संदिग्ध

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

सीधी। चुरहट तहसील के नकवेल में अवैध खनन का कारोबार बेखौफ होकर किया जा रहा है। ऐसा आभाष होता है कि खनन माफियाओं के जेहन से कार्रवाई होने का अंदेशा पूरी तरह से दूर हो चुका है यह तभी संभव है जब जिम्मेदार विभागों के अधिकारियों का संरक्षण मिला हो। ग्रामीणों के अनुसार ग्राम पटवारी हल्का एवं ग्राम नकवेल में अवैध मुरुम एवं मिट्टी उत्खनन का कारोबार खनन माफियाओं द्वारा करने से तहसील कार्यालय से लगी पहाड़ी समतल हो गई है। तहसील परिसर में मौजूद जिम्मेदार अधिकारी पूरी तरह से मूकदर्शक बने हुए हैं। अगर खनिज विभाग से नियमानुसार अनुमति लेकर उत्खनन किया गया होता तो सरकार को लाखों रुपए का राजस्व मिला होता। यहां के जिम्मेदार अधिकारियों ने भूमिस्वामी एवं खनन माफिया से सांठ-गांठ कर सरकार को लाखों रुपए की राजस्व चपत लगाई गई। तहसील चुरहट के पटवारी हल्का नकवेल की लगभग दो हेक्टेयर से अधिक भूमि पर अवैध उत्खनन किया गया है। आराजी नंबर 1439/3/1/1/2/1, 1439/3/1/1/2/1, 1439/3/1/1/2/4/1, 1440/1/1/1/1/1 /1 से अवैध रूप से मुरुम का उत्खनन एवं परिवहन किया गया है। बताया गया है कि चुरहट तहसील अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में अवैध खनन का मामला गत वर्ष भी सुर्खियों में रहा है। तत्कालीन कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने शिकायत कर खनिज विभाग एवं राजस्व विभाग को कार्रवाई के लिए निर्देश दिया था जिसके बाद खनन माफियाओं में हडक़ंप मच गया था लेकिन फिर एक बार चुरहट क्षेत्र में खनन माफिया सक्रिय हो गए हैं। नकवेल पहाड़ी में लंबे समय से मुरुम निकासी का कार्य किया जा रहा है। जिस स्थान पर अवैध उत्खनन एवं परिवहन हो रहा है वहां के समीप ही एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार का कार्यालय है। अधिकारियों का कार्यालय में कई घंटे समय बीतता है फिर भी अवैध खनन की जानकारी खंड स्तरीय अमले व पुलिस के पास नहीं है। स्थानीय लोगों की मानें तो गत वर्ष अवैध उत्खनन की शिकायत पर जांच करने पहुंची टीम के बाद कुछ दिनों के लिए अवैध उत्खनन का कार्य बंद हो गया था। बाद में जैसे ही जांच प्रक्रिया थमी अवैध उत्खनन व परिवहन का कार्य तेजी के साथ शुरू हो गया। लोगों का कहना है कि जिस स्थान पर अवैध उत्खनन एवं परिवहन हो रहा है वहां पर कार्रवाई के लिए जिम्मेदार सभी प्रशासनिक अमला के साथ पुलिस अमला भी मौजूद है।

धडल्ले से जारी है अवैध उत्खनन

चुरहट तहसील के बगल में अवैध मुरूम निकासी का कारोबार फिर धड़ल्ले से शुरू हो गया है। ऐसा नही है कि इस अवैध खनन की जानकारी खंड स्तरीय अमले व पुलिस के पास नही है। लेकिन किसी के द्वारा इस ओर नजर नही दौड़ाई जा रही है। स्थानीय लोगों की माने तो गत वर्ष अवैध उत्खनन की शिकायत पर जांच करने पहुंची टीम के बाद कुछ दिनो के लिए उत्खनन का कार्य बंद हो गया था लेकिन जांच प्रक्रिया जैसे ही थमी हुई उत्खनन का कार्य शुरू हो गया है। लोगों की माने तो यह क्षेत्र जहां तहसील कार्यालय के बगल से लगा हुआ है जहां प्रतिदिन एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित राजस्व अमले का आना जाना बना रहता है। वहीं पुलिस की टीम भी आती-जाती देखी जा रही है। लेकिन किसी के द्वारा इस अवैध उत्खनन पर रोंक लगाने की हिम्मत नही जुटाई जा रही है।

संक्षिप्त समाचार

रूसी राष्ट्रपति पुतिन सितंबर में भारत आएंगे

नई दिल्ली। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसी साल सितंबर में भारत आएंगे। रूसी सरकार ने मंगलवार को कहा कि पुतिन 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले BRICS समिट में हिस्सा लेंगे। PM मोदी ने पुतिन को दिसंबर 2025 में उनके भारत दौरे के दौरान आधिकारिक तौर पर समिट में शामिल होने का न्योता दिया था। एक साल के भीतर पुतिन का यह दूसरा भारत दौरा होगा। पीएम मोदी भी इसी साल रूस दौरे पर जाएंगे। इससे पहले पुतिन दिसंबर 2025 में भारत आए थे। उस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के साथ 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था। 2025 का दौरा इसलिए भी खास माना गया था, क्योंकि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यह पुतिन का पहला भारत दौरा था। इससे पहले वह आखिरी बार 2021 में नई दिल्ली आए थे। इस साल भारत BRICS की अध्यक्षता कर रहा है। BRICS दुनिया की बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जिसमें भारत, रूस, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका के अलावा अब मिस्र, ईरान, इथियोपिया, UAE और इंडोनेशिया जैसे नए सदस्य भी शामिल हो चुके हैं। भारत की अध्यक्षता के दौरान पूरे साल देश के अलग-अलग शहरों में कई बैठकें, मंत्रीस्तरीय सम्मेलन और कार्यकारी समूहों की चर्चाएं आयोजित की जा रही हैं। भारत ने अपनी अध्यक्षता का फोकस 'ग्लोबल साउथ' यानी विकासशील देशों की आवाज को मजबूत करने, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था, आर्थिक सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आतंकवाद विरोधी सहयोग और सप्लाई चेन को मजबूत करने पर रखा है। भारत यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि BRICS सिर्फ राजनीतिक मंच नहीं, बल्कि व्यापार, निवेश, तकनीक और विकास से जुड़ा बड़ा आर्थिक समूह भी बन सकता है।

ट्रम्प-नेतन्याहू की हत्या करने वाले को 500 करोड़ देगा ईरान, संसद में बिल लाने की तैयारी

तेल अवीव/तेहरान/वॉशिंगटन डीसी। ईरान की संसद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या करने वालों को 500 करोड़ से ज्यादा इनाम देने वाला बिल ला सकती है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरानी संसद का राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग इस बिल की तैयारी कर रहा है। आयोग के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने कहा कि 'इस्लामिक रिपब्लिक की सैन्य और सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई' नाम से बिल तैयार किया जा रहा है। ईरानी सांसद महमूद नबावियन ने कहा कि संसद जल्द इस बिल पर वोटिंग कर सकती है, जो ट्रम्प और नेतन्याहू को जहन्नुम पहुंचाने वालों को इनाम देगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई

समेत कई सैन्य और राजनीतिक नेताओं की मौत के बाद यह कदम उठाया जा रहा है। इस बीच ट्रम्प ने कहा है कि उन्होंने ईरान पर मंगलवार को होने वाला हमला फिलहाल टाल दिया है। ट्रम्प ने कहा कि कतर, सऊदी अरब और UAE जैसे गल्फ देशों के नेताओं ने बातचीत को मौका देने के लिए कुछ दिन का समय मांगा था। ट्रम्प ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि घड़ी तेजी से चल रही है और अगर जल्द समझौता नहीं हुआ तो गंभीर नतीजे होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जर्मनी स्थित अमेरिकी ठिकानों से हथियार लेकर दर्जनों कार्गो विमान इजराइल पहुंचे हैं। वहीं नेतन्याहू और ट्रम्प ने संभावित सैन्य कार्रवाई को लेकर बातचीत की।

मानसून अगले हफ्ते केरलम पहुंचेगा, रफ्तार कम रहेगी

भोपाल/जयपुर/लखनऊ/पटना। दक्षिण-पश्चिम मानसून ने भारत की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। फिलहाल यह अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी सिरे से लेकर उत्तरी सिरे तक छा चुका है। मौसम विभाग ने तय तारीख एक जून से पहले 22 से 26 मई के बीच मानसून के केरलम पहुंचने की संभावना जताई है। इस बार मानसून की रफ्तार धीमी रहने की आशंका ज्यादा है। इसलिए लगातार बारिश के बजाय मानसून बार-बार अटकेगा। एक ही जगह ठहरा रहेगा। इसमें बिना बारिश के दिनों की संख्या (मानसून ब्रेक) ज्यादा रह सकती है। जून से सितंबर के दौरान 7 से 14 दिन तक के कई ब्रेक आ सकते हैं। निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट वेदर के अध्यक्ष जीपी शर्मा कहते हैं कि इस बार मानसून पर 2002 जैसा खतरा दिख रहा है। तब मानसून 29 मई को केरल पहुंच गया था। सामान्य रूप से ये 35 से 38 दिनों में पूरे भारत को कवर कर लेता है। लेकिन, 2002 में उसे 79 दिन लगे थे और 15 अगस्त को मानसून पूरे देश में छाया था। इस बीच अगले 7 दिन उत्तर और मध्य भारत के 10 राज्यों में हीटवेव का अलर्ट है। निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक मंगलवार को पूर्वोत्तर और दक्षिणी इलाकों को छोड़कर लगभग आधे देश में हीटवेव का असर रहेगा। औसत तापमान 45°C तक रह सकता है।

ऋषिकेश में उज्जैनी एक्सप्रेस के 3 कोच पटरी से उतरे, शंटिंग के दौरान बफर से टकराया इंजन

ऋषिकेश। ऋषिकेश में सोमवार रात शंटिंग के दौरान उज्जैनी एक्सप्रेस के तीन कोच पटरी से उतर गए। रेलवे सूत्रों के मुताबिक शंटिंग लाइन के अंत में लगे बफर (डेड एंड) से इंजन टकरा गया, जिसके बाद डिब्बों पर दबाव बढ़ गया। इससे एक बोगी ट्रैक से पूरी तरह बाहर निकल गई, जबकि दूसरी बीच से मुड़ गई। जानकारी के मुताबिक उज्जैनी एक्सप्रेस सोमवार शाम करीब 6 बजे योगनगरी रेलवे स्टेशन पहुंची थी। ट्रेन को मंगलवार सुबह 6:15 बजे वापस रवाना होना था। इसी वजह से रात करीब 9:42 बजे ट्रेन को प्लेटफॉर्म से खांड गांव स्थित शंटिंग लाइन पर ले जाया जा रहा था। इसी दौरान हादसा हो गया। हादसे में ट्रेन की तीन बोगियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। हादसे के दौरान जोरदार आवाज सुनकर आसपास के लोग घरों और दुकानों से बाहर निकल आए। घटना के बाद रेलवे अधिकारी, इंजीनियरिंग टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। देर रात तक ट्रैक दुरुस्त करने और क्षतिग्रस्त डिब्बों को हटाने का काम चलता रहा। गनीमत रही कि हादसे के वक्त ट्रेन खाली थी, इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई। उज्जैनी एक्सप्रेस सोमवार शाम योगनगरी रेलवे स्टेशन पहुंची थी। ट्रेन को मंगलवार सुबह वापस रवाना होना था, इसलिए रात करीब 9:42 बजे इसे प्लेटफॉर्म से खांड गांव स्थित शंटिंग लाइन पर ले जाया जा रहा था। इसी दौरान शंटिंग लाइन के अंत में लगे बफर (डेड एंड) से इंजन टकरा गया। इंजन के बफर से टकराने के बाद पूरी ट्रेन झटके के साथ रुक गई और डिब्बों पर दबाव बढ़ गया। दबाव ज्यादा होने से एक बोगी ट्रैक से बाहर निकल गई, जबकि दूसरी बीच से मुड़ गई। हादसे में ट्रेन की तीन बोगियां क्षतिग्रस्त हुईं। डिब्बों के टकराने की जोरदार आवाज सुनकर आसपास के लोग घरों और दुकानों से बाहर निकल आए।

एक्ट्रेस ट्विशा की डेडबॉडी पर मल्टीपल चोटें

भोपाल। भोपाल की एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत मामले ने तूल पकड़ लिया है। एम्स भोपाल की शॉर्ट पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में बॉडी पर मल्टीपल चोटों के निशानों का जिक्र है। ट्विशा के परिजन शुरुआत से हत्या की आशंका जता रहे हैं। वहीं, ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह और उनके वकील इनोश जॉर्ज कार्लो ने रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि रिपोर्ट केवल सेंसेशन फैलाने के इरादे से तैयार की गई है। रिपोर्ट में चोटों का जिक्र है, लेकिन कहां और कितनी चोट हैं, यह स्पष्ट नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि सेकेंड पोस्टमॉर्टम या किसी भी एजेंसी से जांच कराने पर हमें कोई ऐतराज नहीं है। हम जांच में सहयोग करेंगे। मामले में पुलिस जांच पर सवाल उठ रहे हैं। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार जिस बेल्ट से फांसी लगाने की बात कही गई थी, उसे जांच अधिकारी पोस्टमॉर्टम के समय एम्स भोपाल नहीं ले गए थे। बाद में बेल्ट जांच के लिए सौंपी गई, लेकिन डॉक्टर कथित फांसी के साधन और गर्दन के निशानों का वैज्ञानिक परीक्षण नहीं कर सके। पोस्टमॉर्टम में हुई चूक के बाद ट्विशा के परिजन ने मामले की जांच मध्य प्रदेश से बाहर किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने और दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमॉर्टम की मांग की है। इसी वजह से मौत के आठ दिन बाद भी परिजन डेडबॉडी लेने और अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं हैं। परिजन का कहना है कि बेल्ट उपलब्ध नहीं होने से डॉक्टर यह तय नहीं कर सके कि फांसी किस चीज से लगाई गई थी। गर्दन के मार्क्स का सही मिलान और माप भी नहीं हो पाया। इस बीच, पति समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी गई थी।

राहुल बोले, 'देश में अब आने वाला है आर्थिक तूफ़ान'

एजेंसी, रायबरेली

रायबरेली के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं राहुल गांधी

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मंगलवार को अपने दो दिवसीय उत्तर प्रदेश दौरे के पहले दिन रायबरेली में कहा कि देश में अब आर्थिक तूफ़ान आने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो ढांचा बनाया था, वह टूटने वाला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल रायबरेली में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि किसान, छोटे व्यापारी, आम आदमी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ख़ुद विदेश जा रहे हैं जबकि दूसरों को जाने से रोक रहे हैं। दरअसल, राहुल गांधी रायबरेली संसदीय क्षेत्र के दो दिवसीय दौरे पर मंगलवार को रायबरेली पहुंचे हैं। यहां कार्यकर्ताओं ने चूरूवा बॉर्डर पर राहुल गांधी का भव्य स्वागत

किया। चूरूवा बॉर्डर पर स्थित हनुमान मंदिर पर उन्होंने मत्था टेका और आशीर्वाद लिया। इस दौरान बाहर मौजूद कार्यकर्ता उनके पक्ष में नारेबाज़ी कर रहे थे। राहुल इसके बाद बछरावां पहुंचे। भक्तिन खेड़ा गाँव में सांसद निधि से बने बारात घर का उद्घाटन किया। 15 लाख की लागत से बने इस बारात घर का शिलान्यास भी राहुल ने किया था। इसके अलावा राहुल गांधी अन्य कई कार्यक्रमों में प्रतिभाग करेंगे। यहां वह लोगों से सीधे रूबरू होंगे। कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी का लालगंज में महिलाओं के साथ बैठक कर संवाद करने का कार्यक्रम है। मंगलवार शाम को वह भुएमऊ गेस्ट हाउस पहुंचेंगे। जहां रात्रि विश्राम के बाद बुधवार को सुबह जनप्रतिनिधियों के साथ ही संगठन के लोगों व जनता से मुलाकात करेंगे। इसके बाद लोधवारी में बीरा पासी की मुर्ति पर पुष्प अर्पित कर जन प्रतिनिधियों से बात करेंगे। सांसद राहुल गांधी का अमेठी में भी एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही दिवंगत कांग्रेस नेता योगेंद्र मिश्रा के आवास जाएंगे। वहां परिजनों से मुलाकात कर उनको सांत्वना देंगे। इसके बाद लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे।

पंजाब सरकार को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का नोटिस

एजेंसी, नई दिल्ली

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने सोमवार को जनगणना से संबंधित शिकायत पर संज्ञान लेते हुए पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। यह शिकायत राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष हरदीप सिंह गिल द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना को दी गई थी। शिकायत में कहा गया है कि जनगणना प्रक्रिया में वाल्मीकि समुदाय के संदर्भ में अपमानजनक शब्दों के उपयोग से समुदाय में रोष है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आयोग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित विभागों को नोटिस जारी किया है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने जनगणना संचालन निदेशालय, पंजाब के निदेशक तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग, पंजाब सरकार के प्रमुख सचिव को 15 दिनों के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना ने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जातियों के सम्मान, अधिकार और गरिमा की

रक्षा आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आयोग इस विषय पर प्राप्त रिपोर्ट और कार्रवाई के आधार पर आगे आवश्यक कदम उठाएगा।

उल्लेखनीय है कि पंजाब में मादक पदार्थ और सामाजिक-आर्थिक जनगणना का पहला चरण चल रहा है। इसके तहत अधिकारियों द्वारा घर-घर जाकर मकानों की स्थिति, सुविधाओं और संपत्ति से जुड़े 33 सवाल पूछे जा रहे हैं। पहला चरण (हाउस लिस्टिंग और आवास जनगणना) दो भागों में विभाजित था। इसके तहत स्व-गणना की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पूरी की गई। वहीं, 15 मई से 13 जून तक कर्मचारी घर-घर जाकर डेटा संग्रह कर रहे हैं।

राजस्थान में दो बहनों की आत्महत्या मामले में एनसीडब्ल्यू ने लिया संज्ञान

एजेंसी, नई दिल्ली

राष्ट्रीय महिला आयोग ने जोधपुर में दो बहनों के साथ कथित रूप से लंबे समय तक सामूहिक दुष्कर्म, ब्लैकमेल, यौन शोषण एवं बाद में आत्महत्या किए जाने संबंधी मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। अध्यक्ष विजया रहाटकर ने राजस्थान के मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर मामले में तत्काल, निष्पक्ष एवं समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

आयोग ने सात दिनों के भीतर विस्तृत एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। आयोग ने एफआईआर में लगाए गए प्रावधानों, सभी आरोपितों की गिरफ्तारी, जांच की वर्तमान स्थिति, डिजिटल एवं फोरेंसिक साक्ष्यों, पीड़ित परिवार द्वारा पूर्व में की गई शिकायतों पर कथित पुलिस निष्क्रियता तथा संबंधित

अधिकारियों की जवाबदेही संबंधी विवरण मांगे हैं। साथ ही पीड़ित परिवार को उपलब्ध कराई जा रही कानूनी सहायता, मनोवैज्ञानिक परामर्श, सुरक्षा एवं पुनर्वास सहायता तथा भविष्य में महिलाओं से जुड़े यौन अपराधों एवं ब्लैकमेल के मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु उठाए जा रहे कदमों की जानकारी भी मांगी गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि महिलाओं के विरुद्ध इस प्रकार के जघन्य अपराध को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मणिपुर में भारत-म्यांमार सीमावर्ती इलाकों से पीएलए, यूएनएलएफ और केवाईकेएल के कई उग्रवादी गिरफ्तार

एजेंसी, इंफाल

मणिपुर में सुरक्षा बलों और केंद्रीय एजेंसियों ने उग्रवाद विरोधी अभियान तेज करते हुए प्रतिबंधित संगठनों पीएलए, यूएनएलएफ और केवाईकेएल से जुड़े कई सक्रिय उग्रवादियों को भारत-म्यांमार सीमावर्ती इलाकों के अलग-अलग जिलों से बीते 24 घंटे में गिरफ्तार किया है। मणिपुर पुलिस ने मंगलवार को दी गई आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि केंद्रीय बलों ने तेंगनौपाल जिले के मोरेह थाना क्षेत्र में बीपी(बॉर्डर पिलर)-77 और बीपी-79 के बीच अभियान चलाकर पीएलए के तीन सक्रिय कैडरों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार उग्रवादियों की पहचान थोउबल जिले के चरंगपत निवासी वांगथोई नाहाकपम उर्फ लिंगजेल (20), इंफाल पूर्व जिले के कोंगबा निवासी नानाओबा नांदेइबाम उर्फ अंगौ (19) तथा बिष्णुपुर जिले के नाम्बोल निवासी मालेम ओइनाम उर्फ मणिथोइबा (20) के रूप में हुई है।

वहीं, सुरक्षा बलों ने आरपीएफ/पीएलए के

एक सक्रिय सदस्य चिंगलेन अथोकपम उर्फ इबुंगो (30) को भी गिरफ्तार किया। वह इंफाल पूर्व जिले के लामलाई थाना क्षेत्र स्थित पुंगडोंगबाम मयाई लेकाई का निवासी है। वहीं, एक अन्य अभियान में सुरक्षा बलों ने थोउबल जिले के यैरिपोक थाना क्षेत्र अंतर्गत यैरिपोक बाजार इलाके में अभियान चलाकर यूएनएलएफ (कोइरेंग) के सक्रिय उग्रवादी थांगजाम धर्मेंद्र सिंह उर्फ वायेनबा उर्फ वॉल्यूम (26) को गिरफ्तार किया। वह अवैध हथियार और गोला-बारूद की तस्करी में संलिप्त बताया गया है। उसके कब्जे से एक 9 एमएम मैगजीन, एक मोबाइल फोन के साथ दो सिम कार्ड, एक पावर बैंक एवं यूएसबी केबल तथा एक एटीएम कार्ड बरामद किया गया।

इसके अलावा इंफाल पश्चिम जिले के लामफेल थाना क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों से केवाईकेएल के दो सक्रिय कैडरों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार उग्रवादियों में इराम सिफाई मामांग लेकाई निवासी सोरोक्हाइबाम प्रियचंद सिंह उर्फ सजाओ (39) तथा उरीपोक ताखेल्लामबाम लेकाई निवासी मोइरंगथेम नाओबी सिंह (47) शामिल हैं। प्रियचंद सिंह को रिम्स के निकट से जबकि नाओबी सिंह को उसके आवास से गिरफ्तार किया गया। सुरक्षा बलों ने इनके पास से दो मोबाइल फोन और एक आधार कार्ड भी बरामद किया है।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा- "सत्य को दबाया नहीं जा सकता"

एजेंसी, कोलकाता

आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में चिकित्सक-छात्रा के कथित दुष्कर्म और हत्या मामले में राज्य सरकार ने अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुमति प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार रात एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए इसे "न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम" बताया। मुख्यमंत्री ने पोस्ट पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के विशेष सचिव द्वारा जारी आदेश की प्रति भी साझा की। चूंकि संदीप घोष सरकारी कर्मचारी हैं, इसलिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक थी।

मुख्यमंत्री अधिकारी ने लिखा कि आरजी कर अस्पताल में नौ अगस्त 2024 को हुई चिकित्सक-छात्रा की "निर्मम हत्या और दुष्कर्म" की घटना में तत्कालीन प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया के तहत ईडी को कार्रवाई की अनुमति प्रदान की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती तृणमूल सरकार ने इस मामले की जांच प्रक्रिया को

लंबे समय तक रोके रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का मानना है कि "कानून से ऊपर कोई नहीं है और सत्य को हमेशा दबाकर नहीं रखा जा सकता।"

आदेश में कहा गया है कि राज्यपाल एवं सक्षम प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों और साक्ष्यों की विस्तृत जांच के बाद प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि तत्कालीन प्राचार्य संदीप घोष की आपराधिक गतिविधियां और कर्तव्य में लापरवाही भारतीय न्याय संहिता की धारा 120बी के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 420 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा सात के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आती हैं। इसके साथ ही धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत

आरजी कर मामले में बड़ा कदम, संदीप घोष के खिलाफ अभियोजन की अनुमति

भी मामला दर्ज किए जाने योग्य पाया गया है। इसी आधार पर संदीप घोष के साथ-साथ "मा तारा ट्रेडर्स", "ईशान कैफे" और "खामा लोहा" के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच शुरू की गई है। सरकारी आदेश की प्रति राज्य के मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव, प्रवर्तन निदेशालय के सहायक निदेशक तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई है। उधर, पीड़िता की मां, जो हाल ही में पानीहाटी से भाजपा विधायक निर्वाचित हुई हैं, ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से शामिल अन्य लोगों को भी जांच के दायरे में लाने की मांग की है। पीड़िता के माता-पिता लगातार दावा करते रहे हैं कि इस घटना में केवल दोषी करार दिया गया संजय राय ही शामिल नहीं था, बल्कि कई अन्य लोग भी इसमें संलिप्त थे। परिजनों ने आरोप लगाया है कि शव का जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कर सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी।

मेसी टूर ऑर्गनाइजर का बंगाल के मंत्री पर केस

एजेंसी, कोलकाता

फुटबॉलर लियोनेल मेसी के कोलकाता दौरे के ऑर्गनाइजर सताद्रु दत्ता ने 4 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इनमें TMC नेता और ममता सरकार के पूर्व खेल मंत्री अरूप बिस्वास का नाम भी शामिल है। शिकायत में पूर्व DGP और TMC राज्यसभा सांसद राजीव कुमार, कोलकाता नगर निगम पार्षद जुईन बिस्वास और सूचना एवं संस्कृति विभाग के सचिव शांतनु बसु के नाम हैं।

दत्ता ने आरोप लगाया कि दिसंबर 2025 में साल्ट लेक स्टेडियम में हुए मेसी कार्यक्रम के दौरान हुई अव्यवस्था और हंगामे के लिए ये लोग जिम्मेदार थे।

अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी 3 दिन के भारत दौरे पर आए थे। 13 दिसंबर की देर रात करीब 2:30 बजे वह कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे थे। अगले दिन सुबह 11 बजे मेसी ने कोलकाता में अपनी

70 फीट ऊंची प्रतिमा का वर्चुअल उद्घाटन किया था।

मेसी को साल्ट लेक स्टेडियम में करीब 1 घंटे रुकना था, लेकिन वह 22 मिनट बाद ही वहां से निकल गए। इससे नाराज फैंस ने स्टेडियम में कुर्सियां फेंककर तोड़फोड़ की थी। इस दौरान भगदड़ जैसे हालात भी बन गए थे।

दत्ता को 13 दिसंबर को कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में हुई तोड़फोड़ के मामले में हिरासत में लिया गया था। 37 दिन जेल में रहने के बाद 19 जनवरी को बिधाननगर कोर्ट से उन्हें जमानत मिली थी।

मप्र के सतना में सॉल्वेंट प्लांट में आग लगने जिंदा जला मजदूर

आक्रोशित लोगों ने किया चक्काजाम

एजेंसी, सतना

मध्य प्रदेश के सतना जिले में अमरपाटन रोड स्थित विद्याश्री सॉल्वेंट प्लांट (तेल मिल) में सोमवार देर रात अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से एक कर्मचारी जिंदा जल गया, जबकि दूसरा गंभीर रूप से झुलस गया। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर हाइवे पर चक्काजाम कर दिया। क्षेत्र के सीएसपी डीपी सिंह चौहान ने बताया कि अमरपाटन रोड पर भटनवारा के पास स्थित विद्याश्री साल्वेंट प्लांट में सोमवार की रात अज्ञात कारणों से आग लग गई। प्लांट में धान की भूसी से राइस ब्रान ऑयल बनाया जाता था। इसलिए आग धान की भूसी और तेल के संपर्क में आकर इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरा परिसर लपटों से घिर गया। उन्होंने

बताया कि घटना के समय मौके पर 4 से 5 कर्मचारी मौजूद थे, जिनमें से कुछ तो बाहर की तरफ भाग निकले, मगर तिघरा निवासी मशीन ऑपरेटर दिलावर सिंह परिहार और मुन्नू केवट अंदर ही फंस गए। आग इतनी भीषण थी कि कई किलोमीटर दूर से उसकी लपटें देखी जा सकतीं थीं। इस बीच आगजनी की खबर लगते ही पुलिस टीम के साथ नगर निगम के दमकल वाहन मौके पर पहुंचे, जिनकी मदद से बचाव के प्रयास शुरू किए गए। नगर निगम के दमकल कर्मियों ने लगभग चार घंटे तक जद्दोजहद करते हुए आग पर काबू पाया।

केंद्रीय गृहमंत्री शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक शुरू, चार राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल

एजेंसी, जगदलपुर

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज मंगलवार को जगदलपुर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं उच्चस्तरीय बैठक शुरू हो गई है। इसमें छत्तीसगढ़ सहित चार राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। बस्तर में पहली बार हो रही इस महत्वपूर्ण बैठक को सुरक्षा, विकास और राज्यों के बीच समन्वय के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।

प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां कार्यक्रम को लेकर पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं। जगदलपुर शहर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। बैठक में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह

धामी का आत्मीय स्वागत किया। वहीं उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री यागी आदित्यनाथ आज मंगलवार सुबह जगदलपुर पहुंच गये हैं। मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के आगमन के बाद एयरपोर्ट से लेकर बैठक स्थल तक सुरक्षा एजेंसियों की विशेष निगरानी की जा रही है।

इस बैठक में कई अहम विषयों पर विस्तृत मंथन किया जाएगा। इनमें अंतरराज्यीय समन्वय, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण योजनाएं, बिजली और शहरी विकास, सहकारिता और प्रशासनिक सहयोग शामिल हैं। बताया जा रहा है कि राज्यों के बीच बेहतर तालमेल और विकास परियोजनाओं को तेज गति देने के लिए साझा रणनीति तैयार की जा सकती है। राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। परिषद की बैठक के बाद बस्तर सहित मध्य क्षेत्र के राज्यों में विकास परियोजनाओं को नई रफ्तार मिल सकती है। इसके साथ ही नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और समन्वित कार्रवाई के लिए बड़ा रोडमैप तैयार होने की भी संभावना है। कभी नक्सली घटनाओं के कारण चर्चा में रहने वाला बस्तर अब तेजी से विकास और शांति की दिशा में आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय स्तर की इस बड़ी बैठक का आयोजन बस्तर की बदलती पहचान का संकेत माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर में इस तरह की उच्चस्तरीय बैठक का आयोजन पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि अब बस्तर शांति, विश्वास और विकास की नई पहचान बनता जा रहा है।

आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक रुख-19 मई 2026 को सभी याचिकाएं खारिज- संविधान के अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या- जनसुरक्षा बनाम पशु अधिकार की बहस में नया मोड़

लोकतंत्र की शान

» सुप्रीम कोर्ट द्वारा 19 मई 2026 को दिया गया निर्णय आने वाले समय में नगर निकायों, राज्य सरकारों, पशु कल्याण संगठनों और नागरिक समाज के लिए एक बड़ी परीक्षा साबित होगा

» भारतीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा19 मई 2026 क़ा फैसला भारतीय न्यायिक इतिहास में केवल "डॉग बाइट केस" नहीं बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21की व्यापक व्याख्या सार्वजनिक सुरक्षा और पशु अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करने वाले ऐतिहासिक निर्णय के रूप में याद किया जाएगा -एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर भारत में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या, डॉग बाइट की घटनाओं, रेबीज संक्रमण और सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर वर्षों से चल रही बहस को 19 मई 2026 को एक निर्णायक मोड़ तब मिला जब भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने डॉग लवर्स,पशु अधिकार कार्यकर्ताओं और विभिन्न गैर- सरकारी संगठनों द्वारा दायर उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग की गई थी। यह मामला केवल कुत्तों के पुनर्वास या नसबंदी तक सीमित नहीं था, बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नागरिकों के भयमुक्त और सुरक्षित जीवन के अधिकार तथा पशु संरक्षण के बीच संतुलन की सबसे बड़ी संवैधानिक बहस बन गया। अदालत ने साफ कहा कि स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों, खेल परिसरों और अन्य भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों की मौजूदगी को सामान्य नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा सर्वोपरि है तथा राज्य सरकारें केवल दर्शक बनकर नहीं रह सकतीं। इसी कारण सर्वोच्च अदालत ने नवंबर 2025 के आदेश में किसी भी प्रकार की ढील देने से इनकार करते हुएअपने फैसले को तीन भागों,पार्ट 1,पार्ट 2 और पार्ट 3 में विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया। साथियों मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि यह फैसला ऐसे समय आया है जब देश के अनेक राज्यों में डॉग बाइट के मामले भयावह स्तर तक पहुंच चुके हैं। अदालत के समक्ष रखे गए आंकड़ों के अनुसार राजस्थान के श्रीगंगानगर में केवल 30 दिनों में 1084 डॉग बाइट के मामले सामने आए,जबकि तमिलनाडु में मात्र चार महीनों में दो लाख से अधिक डॉग बाइट के केस दर्ज किए गए। अदालत ने टिप्पणी की कि यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातस्थिति का संकेत है। न्यायालय ने कहा कि जब छोटे बच्चों के चेहरे नोचे जा रहे हों, बुजुर्गों पर झुंड बनाकर हमले हो रहे हों और अस्पतालों तक पहुंचने वाले मरीज रेबीज के भय में जी रहे हों, तब अदालत जमीनी वास्तविकताओं से आंखें नहीं मूंद सकती। यही कारण है कि इस फैसले को भारत में आवारा कुत्तों की नीति के इतिहास में एक ऐतिहासिक और निर्णायक निर्णय माना जा रहा है। साथियों फैसले के पहले भाग में सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों, पशु जन्म नियंत्रण (एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) रूल्स 2023 तथा भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों (एसओपी) की समीक्षा की। अदालत ने पाया कि अधिकांश राज्यों में नसबंदी, टीकाकरण, पुनर्वास और शेल्टर प्रबंधन की स्थिति बेहद कमजोर और असंगठित है। कई राज्यों में एंटी-रेबीज वैक्सीन की भारी कमी पाई गई, प्रशिक्षित पशु चिकित्सकों और तकनीकी स्टाफ का अभाव सामने आया तथा नगर निकायों के बीच समन्वय की कमी भी उजागर हुई।अदालत ने टिप्पणी की कि प्रशासनिक उदासीनता और नीतिगत विफलताओं के कारण ही डॉग बाइट की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि एनिमल बर्थ कंट्रोल नियमों का समय पर और प्रभावी तरीके से पालन किया गया होता, तो आज स्थिति इतनी भयावह नहीं बनती। साथियों फैसले के दूसरे भाग में अदालत ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ़ इंडिया (एडब्लूबीआई) द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) और उससे जुड़े कानूनी ढांचे पर विस्तार से विचार किया। डॉग लवर्स और पशु अधिकार संगठनों की ओर से यह तर्क रखा गया कि नसबंदी और टीकाकरण के बाद कुत्तों को उसी स्थान पर वापस छोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा न करने से क्षेत्रीय संघर्ष बढ़ सकते हैं तथा यह पशु क्रूरता की श्रेणी में आएगा। याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 तथा अनुच्छेद 51ए (ज़ी) का उल्लेख करते हुए कहा कि नागरिकों का यह मौलिक कर्तव्य है कि वे पशुओं के प्रति करुणा रखें। कुछ वकीलों ने 1960के पशु क्रूरता निवारण कानून तथा 1965 के पशु श्रम संबंधी प्रावधानों का भी हवाला दिया, जिनमें जानवरों के साथ अमानवीय व्यवहार को प्रतिबंधित किया गया है। फैसले के बाद एक्टिविस्टो ने प्रेस के समक्ष यह भी तर्क रखा गया कि देश में गौशालाओं की बदहाल स्थिति, सड़कों पर पशुओं की मृत्यु तथा बूचड़खानों की वास्तविकताओं पर भी समान संवेदनशीलता दिखाई जानी चाहिए।सर्वोच्च अदालत ने इन दलीलों को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि पशु संरक्षण महत्वपूर्ण है, परंतु सार्वजनिक सुरक्षा उससे कम महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि संविधान का अनुच्छेद 21 केवल जीवित रहने का अधिकार नहीं देता, बल्कि यह भयमुक्त और सम्मानजनक जीवन का अधिकार भी प्रदान करता है। यदि कोई बच्चा स्कूल जाते समय कुत्तों के झुंड के भय में जी रहा है, यदि बुजुर्ग पार्क या सड़क पर निकलने से डर रहे हैं, यदि अस्पतालों और बस स्टैंडों के आसपास लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो राज्य का संवैधानिक दायित्व है कि वह नागरिकों की रक्षा करे। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता यह सिद्ध नहीं कर पाए कि एडब्लूबीआई की एसओपी संविधान या किसी कानून के विरुद्ध है। इसलिए सभी याचिकाएं खारिज की जाती हैं। साथियों फैसले के तीसरे भाग में सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक संस्थानों और संवेदनशील क्षेत्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए। अदालत ने आदेश दिया कि स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, खेल परिसरों, रेलवे स्टेशनों, बस डिपो, एयरपोर्ट तथा अन्य भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक क्षेत्रों से पकड़े गए आवारा कुत्तों को दोबारा उसी स्थान पर नहीं छोड़ा जाएगा। उन्हें उचित शेल्टर होम्स या पुनर्वास केंद्रों में रखा जाएगा। अदालत ने राज्यों और स्थानीय निकायों को निर्देश दिया कि वे पर्याप्त संख्या में आधुनिक शेल्टर होम्स स्थापित करें, जहां कुत्तों के भोजन,चिकित्सा, नसबंदी और टीकाकरण की समुचित व्यवस्था हो। साथ ही न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि रेबीज संक्रमित या अत्यधिक आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें आवश्यक परिस्थितियों में एउथानसया अर्थात इच्छामृत्यु भी शामिल हो सकती है।सर्वोच्च अदालत की यह टिप्पणी विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही कि "लोगों की जान सबसे पहले है।" अदालत ने कहा कि पशु अधिकारों की रक्षा के नाम पर मानव जीवन और सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरे में नहीं डाला जा सकता। यह टिप्पणी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में देशभर में डॉग फीडिंग और आवारा कुत्तों के संरक्षण को लेकर अनेक सामाजिक संघर्ष सामने आए हैं। कई स्थानों पर निवासी संघों और डॉग लवर्स के बीच विवाद अदालतों तक पहुंचे। कुछ मामलों में बच्चों और बुजुर्गों पर हमलों के बाद स्थानीय स्तर पर हिंसक प्रतिक्रियाएं भी देखी गईं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले के माध्यम से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि पशु संरक्षण और जनसुरक्षा के बीच संतुलन आवश्यक है, लेकिन सटीक प्राथमिकता नागरिकों के जीवन और सुरक्षा को दी जाएगी। साथियों अदालत ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश भी दिया कि वे नए एनिमल बर्थ कंट्रोल (एसओपी) केंद्र स्थापित करें तथा पर्याप्त मात्रा में एंटी-रेबीज वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करें न्यायालय ने कहा कि केवल कुत्तों को पकड़कर स्थानांतरित कर देना समाधान नहीं है। आवश्यक है कि वैज्ञानिक तरीके से नसबंदी, टीकाकरण, पुनर्वास और जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम चलाए जाएं। अदालत ने यह भी कहा कि नगर निकायों और राज्य सरकारों को डेटा आधारित नीति बनानी होगी, ताकि डॉग बाइट के मामलों, रेबीज संक्रमण और सार्वजनिक जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान कर समयबद्ध कार्रवाई की जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि नवंबर 2025 के आदेश का सही ढंग से पालन नहीं किया गया। अदालत ने इसे अवमानना के रूप में देखने की चेतावनी दी और कहा कि यदि भविष्य में भी आदेशों की अनदेखी हुई तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक औरअवमानना की कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही उच्च न्यायालयों को स्वतः संज्ञान यानी सु मोटो मामलों के माध्यम से निगरानी बनाए रखने का निर्देश दिया गया। यह निर्देश इस बात का संकेत है कि सर्वोच्च अदालत अब इस मुद्दे को केवल नगर निगमों का प्रशासनिक मामला नहीं बल्कि राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और संवैधानिक अधिकारों कासटीक प्रश्न मान रही है। साथियों इस पूरे विवाद में मेंनका गाँधी की प्रतिक्रिया भी चर्चा का विषय बनी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कोई नई बात नहीं है और नवंबर 2025 के आदेश का वास्तविक पालन करना लगभग असंभव है। उनके अनुसार यदि देशभर में आवारा कुत्तों के लिए पर्याप्त शेल्टर होम्स, चिकित्सा सुविधाएं और पुनर्वास केंद्र बनाने हों तो इसके लिए लगभग तीन लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी, जो वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में संभव नहीं दिखाई देता। उन्होंने यह भी कहा कि रेबीज संक्रमित या अत्यधिक बीमार कुत्तों को एउथानसया देने का प्रावधान पहले से ही कानून में मौजूद है,लेकिन उसकी प्रक्रिया जटिल और सख्त नियमों से नियंत्रित है। इसलिए व्यवहारिक स्तर पर इस आदेश को लागू करना आसान नहीं होगा। साथियों, वास्तव में यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा व्यावहारिक प्रश्न है। भारत में अनुमानित करोड़ों की संख्या में मौजूद आवारा कुत्तों के लिए पर्याप्त शेल्टर,पशु चिकित्सालय प्रशिक्षित स्टाफ और वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करना एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य है। नगर निकाय पहले ही वित्तीय संकट, कचरा प्रबंधन,जल निकासी और शहरी अव्यवस्था जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे में व्यापक स्तर पर डॉग शेल्टर प्रणाली खड़ी करना केवल न्यायिक आदेश से संभव नहीं होगा, बल्कि इसके लिए केंद्र और राज्यों के बीच समन्वित नीति, भारी बजटीय निवेश तथा दीर्घकालिक शहरी नियोजन की आवश्यकता होगी।इसके साथ ही यह फैसला भारत में पशु अधिकार आंदोलन के लिए भी एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है। अब तक अदालतें सामान्यतः पशु संरक्षण के पक्ष में संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाती रही हैं, लेकिन इस मामले में सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट किया कि पशु अधिकारों की व्याख्या मानव जीवन के अधिकार को कमजोर करके नहीं की जा सकती। अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 51ए (ज़ी) के अंतर्गत पशुओं के प्रति करुणा के नागरिक कर्तव्य को स्वीकार किया, लेकिन यह भी कहा कि यह कर्तव्य सार्वजनिक सुरक्षा और जनहित से ऊपर नहीं हो सकता। साथियों अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें तो अनेक देशों ने आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए अलग-अलग मॉडल अपनाए हैं। यूरोप के कई देशों में व्यापक शेल्टर प्रणाली, अनिवार्य पंजीकरण और पालतू पशुओं पर कठोर नियम लागू हैं। कुछ देशों में आक्रामक और संक्रमित कुत्तों के एउथानसया की स्पष्ट नीति है। वहीं कई एशियाई देशों में नसबंदी और टीकाकरण आधारित मॉडल अपनाया गया है। भारत की स्थिति इन दोनों के बीच फंसी हुई दिखाई देती है, जहां पशु अधिकार, धार्मिक-सांस्कृतिक संवेदनाएं, शहरी अव्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा एक-दूसरे से टकराते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इसी जटिल संतुलन को स्थापित करने का प्रयास माना जा सकता है। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे क़ि यह निर्णय आने वाले समय में नगर निकायों,राज्य सरकारों, पशु कल्याण संगठनों और नागरिक समाज के लिए एक बड़ी परीक्षा साबित होगा। यदि अदालत के निर्देशों के अनुरूप आधुनिक शेल्टर होम्स, प्रभावी नसबंदी कार्यक्रम, व्यापक टीकाकरण और वैज्ञानिक पुनर्वास नीति विकसित नहीं की गई, तो यह फैसला केवल कागजों तक सीमित रह सकता है। दूसरी ओर यदि राज्यों ने इसे गंभीरता से लागू किया, तो संभव है कि भारत में पहली बार आवारा कुत्तों की समस्या को एक समन्वित सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति के रूप में देखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतिम शब्दों में यह स्पष्ट कर दिया कि अदालत न तो पशुओं के खिलाफ है और न ही पशु प्रेमियों की भावनाओं को अस्वीकार करती है, लेकिन जब प्रश्न नागरिकों की जान, बच्चों की सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य का हो, तब राज्य की पहली जिम्मेदारी मनुष्यों के जीवन की रक्षा करना है। यही कारण है कि 19 मई 2026 का यह फैसला भारतीय न्यायिक इतिहास में केवल "डॉग बाइट केस" नहीं बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या, सार्वजनिक सुरक्षा और पशु अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करने वाले ऐतिहासिक निर्णय के रूप में याद किया जाएगा।

-संकलनकर्ता लेखक - क़र विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यमा सीए(एटीसी) एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र
9284141425

कृषि आधारित उद्योग है मधुमक्खी पालन

लेखक - संजय गोस्वामी

विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल 20 मई को मनाया जाता है इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण, खाद्य सुरक्षा और जैव विविधता को बनाए रखने में मधुमक्खियों और अन्य परागणकों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना हैमधुमक्खी एक सामाजिक कीट का सबसे अच्छा उदाहरण है जो शहद इकट्ठा करती है और अपने परिवार का भरण-पोषण करती है। यह कीट हाइमनोप्टेरा गण के एपिस परिवार के अंतर्गत आता है। भारत में मधुमक्खियों की तीन प्रजातियाँ पाई जाती हैं, भारतीय मधुमक्खी (एपिस इंडिका), रॉक शहद मधुमक्खी (एपिस डोरसोटा) और छोटी शहद मधुमक्खी (एपिस फ्लोरिया)। एक विदेशी शहद मधुमक्खी (एपिस मेलिफेरा) जिसे इटालियन या यूरोपीय शहद मधुमक्खी कहा जाता है, अब भारत में स्थापित हो गई है और इसका उपयोग व्यावसायिक मधुमक्खी पालन के लिए किया जा रहा है। मधुमक्खियों के प्रकार - मधुमक्खियों की उपरोक्त चार प्रजातियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है - (1) भारतीय शहद मधुमक्खी (एपिस सेराना इंडिका) - यह शहद मधुमक्खी पूरे भारत में पाई जाती है। यह पीले भूरे रंग की होती है। यह पुरानी इमारतों, जंगलों, पेड़ों की खोखली दीवारों, गुफाओं आदि जैसे अंधेरे स्थानों में 6-8 समानांतर छत्ते बनाती है। ये मधुमक्खियां स्वभाव से कोमल और शांत होती हैं और इन्हें आसानी से पाला जा सकता है। मधुमक्खी पालक इन्हें प्राकृतिक घरों से पकड़ते हैं और मधुमक्खी के बक्सों में पालते हैं। यह एक उद्यमी मधुमक्खी है तथा अच्छी मात्रा में शहद एकत्रित करती है। औसतन प्रति वर्ष एक कॉलोनी से 2-3 किलोग्राम शहद प्राप्त होता है। (2) रॉक मधुमक्खी (एपिस डोरसाटा)- इस मधुमक्खी को भौंरा या भौंरा भी कहते हैं। यह सम्पूर्ण भारत में पाई जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में यह समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊँचाई तक पाई जाती है। इसकी कॉलोनियाँ कम तापमान पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं। ये मधुमक्खियाँ एक ही छत्ता बनाती हैं जो लगभग 1.5 से 2.1 मीटर चौड़ा तथा 0.6 से 1.2 मीटर लंबा होता है। इनका छत्ता आमतौर पर चट्टानों पर लटका होता है। ये मधुमक्खियाँ बहुत आक्रामक स्वभाव की होती हैं तथा परेशान करने पर मनुष्यों का पीछा कर उन पर हमला कर देती हैं। ये बड़ी मात्रा में शहद एकत्रित करती हैं। ये अपना काम सुबह जल्दी शुरू कर देती हैं। प्रति वर्ष एक छत्ते से 40 किलोग्राम तक शहद प्राप्त होता है। शहद आमतौर पर छत्ते के अगले भाग में मिलता है। (3) छोटी मधुमक्खी -एपिस फ्लोरिया) - यह मधुमक्खी पूरे देश में पाई जाती है लेकिन समुद्र तल से 335 मीटर की ऊंचाई पर बहुत कम पाई जाती है। यह बार-बार अपना स्थान बदलती रहती है तथा इसकी कॉलोनी एक छत्ते पर 5 महीने से अधिक नहीं रहती। यह मधुमक्खी एक छत्ता बनाती है जिसका आकार हथेली के बराबर होता है। यह अपना छत्ता शाखाओं, बाड़ों, पेड़ों, गुफाओं, घरों की चिमनियों, खाली बक्सों, लकड़ियों के ढेर आदि पर बनाती है। इसकी रानी सुनहरे भूरे रंग की होती है। मधुमक्खी पालन एक कृषि आधारित उद्योग है, जिसकी जानकारी बहुत सरल है। इसमें लागत कम, आमदनी अधिक तथा कम समय में अधिक लाभ प्राप्त होता है। गांवों में आर्थिक विकास के लिए मधुमक्खी पालन से अच्छा कोई घरेलू रोजगार नहीं है। जानकारी की सहजता के कारण कम पढ़ा-लिखा व्यक्ति भी इस व्यवसाय को कुशलता से कर सकता है। गरीब, भूमिहीन भी 5 से 10 मधुमक्खी बक्सों की कम पूंजी से यह व्यवसाय शुरू कर 3 साल के भीतर 50-100 बक्सों का मालिक बन सकता है तथा मधुमक्खियां, मोम व शहद बेचकर सालाना लाखों रुपए कमा सकता है। चूंकि इस काम में ज्यादा शारीरिक मेहनत की जरूरत नहीं होती, इसलिए ग्रामीण महिलाएं और बच्चे अपने घरेलू कामों के साथ इसे आसानी से कर सकते हैं। चूंकि इसमें ज्यादा पूंजी की जरूरत नहीं होती, इसलिए बेरोजगार युवा भी इसे अपने रोजगार का जरिया बना सकते हैं। मधुमक्खी पालन से गांवों में मधुमक्खी के बक्से और अन्य उपकरण बनाने वाले छोटे उद्योगों को भी बढ़ावा मिलता है।

खाड़ी देशों में आखिर अमेरिका ने क्यों बनाए सैन्य अड्डे? सुरक्षा की गारंटी या अपने हितों की रणनीति?

सैयद इसरार हुसैन

मध्य पूर्व के खाड़ी देशों में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी लंबे समय से वैश्विक राजनीति का अहम विषय रही है। सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डों की मौजूदगी केवल सुरक्षा सहयोग तक सीमित नहीं मानी जाती, बल्कि इसे अमेरिका की व्यापक रणनीतिक और आर्थिक नीति का हिस्सा भी समझा जाता है। सवाल यह है कि आखिर अमेरिका खाड़ी क्षेत्र में किसकी हिफाजत करना चाहता है — अपने सहयोगी देशों की, वैश्विक तेल आपूर्ति की, या फिर अपने राष्ट्रीय हितों की?

कब और क्यों बढ़ी अमेरिकी मौजूदगी? खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी 1990 के दशक के बाद तेजी से बढ़ी। इराक-कुवैत युद्ध और बाद में खाड़ी युद्ध के दौरान अमेरिका ने इस क्षेत्र में स्थायी सैन्य ढांचे को मजबूत करना शुरू किया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था तेल आपूर्ति की सुरक्षा और मध्य पूर्व में अपने प्रभाव को बनाए रखना। दरअसल, दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। अमेरिका भले ही आज ऊर्जा के मामले में पहले से अधिक आत्मनिर्भर हो चुका हो, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था अब भी खाड़ी के तेल पर काफी हद तक निर्भर है। ऐसे में अमेरिका नहीं चाहता कि इस क्षेत्र में अस्थिरता पैदा हो या तेल आपूर्ति बाधित हो। **अमेरिका की नजर सिर्फ सुरक्षा पर नहीं<-** विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिकी सैन्य अड्डों का उद्देश्य केवल खाड़ी देशों की रक्षा करना नहीं है। इन अड्डों के जरिए अमेरिका पूरे मध्य पूर्व की राजनीतिक और सैन्य गतिविधियों पर नजर बनाए रखता है। यही सैन्य ठिकाने अमेरिका को ईरान, इराक, सीरिया और अफगानिस्तान जैसे क्षेत्रों में तेजी से सैन्य कार्रवाई करने की क्षमता भी देते हैं। कतर का अल-उदीद एयर बेस, बहरीन में अमेरिकी नौसेना का मुख्यालय और कुवैत में तैनात अमेरिकी सैनिक इस रणनीति का हिस्सा माने जाते हैं। इन सैन्य अड्डों की मदद से अमेरिका न केवल अपने सहयोगियों को सुरक्षा का भरोसा देता है, बल्कि क्षेत्र में अपनी ताकत और प्रभाव भी कायम रखता है।

ईरान सबसे बड़ा कारण? खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी के पीछे ईरान एक बड़ा कारण माना जाता है। अमेरिका और ईरान के बीच दशकों से तनाव बना हुआ है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने, मिसाइल कार्यक्रम बढ़ाने और अपने समर्थित संगठनों के जरिए प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करता है। इसी वजह से अमेरिका खुद को खाड़ी देशों की सुरक्षा का संरक्षक बताता है। सऊदी अरब और यूएई जैसे देश भी ईरान की बढ़ती सैन्य ताकत को लेकर चिंतित रहते हैं, इसलिए वे अमेरिकी सुरक्षा सहयोग को अपने लिए जरूरी मानते हैं। हालांकि, आलोचकों का कहना है कि अमेरिका इस खतरे को अपने रणनीतिक हितों के लिए भी इस्तेमाल करता है, ताकि उसकी सैन्य मौजूदगी और राजनीतिक पकड़ क्षेत्र में बनी रहे।

क्या अमेरिका सिर्फ अपना हित देखता है?

इस सवाल पर दुनिया दो हिस्सों में बंटी नजर आती है। एक पक्ष मानता है कि अमेरिका की मौजूदगी ने खाड़ी क्षेत्र में संतुलन बनाए रखा है और बड़े युद्धों को रोकने में भूमिका निभाई है। वहीं दूसरा पक्ष इसे अमेरिका की 'भूराजनैतिक रणनीति' मानता है, जिसका मकसद तेल, व्यापार मार्गों और क्षेत्रीय राजनीति पर नियंत्रण बनाए रखना है। कई विश्लेषकों का मानना है कि अगर अमेरिका वास्तव में केवल सुरक्षा चाहता, तो वह क्षेत्रीय देशों को आत्मनिर्भर रक्षा व्यवस्था विकसित करने के लिए अधिक प्रोत्साहित करता। लेकिन लगातार सैन्य अड्डों का विस्तार यह संकेत देता है कि अमेरिका मध्य पूर्व में अपना प्रभाव कमजोर नहीं होने देना चाहता।

बदलती दुनिया में नई चुनौती -अब वैश्विक राजनीति तेजी से बदल रही है। चीन और रूस भी मध्य पूर्व में अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं। ऐसे में अमेरिका के लिए खाड़ी क्षेत्र केवल सुरक्षा का मामला नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन की लड़ाई का हिस्सा भी बन चुका है। खाड़ी देश भी अब केवल एक शक्ति पर निर्भर नहीं रहना चाहते। वे अमेरिका के साथ संबंध बनाए रखते हुए चीन, रूस और अन्य देशों के साथ भी अपने रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। यही कारण है कि आने वाले वर्षों में खाड़ी क्षेत्र की राजनीति और अधिक जटिल हो सकती है। खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डे केवल सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति, तेल अर्थव्यवस्था और रणनीतिक शक्ति संतुलन का बड़ा प्रतीक हैं। अमेरिका अपने सहयोगियों की सुरक्षा की बात जरूर करता है, लेकिन इसके साथ-साथ वह अपने आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य हितों को भी साधता दिखाई देता है। यही वजह है कि खाड़ी क्षेत्र आज भी विश्व राजनीति का सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है।

मधुमक्खियां, मानव और प्रकृति : साझी जिम्मेदारी

लेखक- सुनील कुमार महला

प्रतिवर्ष 20 मई को संयुक्त राष्ट्र(यूएन) द्वारा घोषित विश्व मधुमक्खी दिवस (वर्ल्ड बी डे) मनाया जाता है। वास्तव में इस दिवस को मनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य मधुमक्खियों और अन्य परागणकर्ताओं के महत्व के प्रति आम लोगों को जागरूक करना तथा उनके संरक्षण की दिशा में वैश्विक प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। हमें यह बात अपने जेहन में रखनी चाहिए कि मधुमक्खियां केवल और केवल शहद बनाने वाली छोटी सी जीव मात्र ही नहीं हैं, बल्कि वे इस पृथ्वी पर जीवन, खाद्य सुरक्षा, जैव- विविधता और पारिस्थितिक संतुलन की अत्यंत महत्वपूर्ण व अहम् कड़ी हैं। कहना ग़लत नहीं होगा कि यदि मधुमक्खियों का अस्तित्व संकट में पड़ता है, तो मानव जीवन, कृषि और पर्यावरण भी गंभीर संकट में आ जाएंगे। इसलिए मधुमक्खियों का संरक्षण केवल और केवल पर्यावरणीय आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि उनका जीवन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में कहीं न कहीं मानव अस्तित्व की भी अहम् आवश्यकता है। अतः हमें अधिक से अधिक पेड़-पौधे लगाने, धरती से रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग को कम करने, जैविक खाद का अधिक उपयोग करने, जैविक खेती अपनाने तथा प्राकृतिक जैव-विविधता को बचाने की दिशा में अपने सामूहिक व यथेष्ठ प्रयास करने होंगे। पाठक जानते होंगे कि खेती, जैव-विविधता और खाद्य सुरक्षा में मधुमक्खियों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वास्तव में, इस दिवस को मनाने के प्रमुख उद्देश्यों में मधुमक्खियों और अन्य परागणकर्ताओं के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना, जैव-विविधता और खाद्य-सुरक्षा की रक्षा करना, मधुमक्खियों पर मंडरा रहे खतरों जैसे कि खेती में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और उनके प्राकृतिक आवासों के विनाश की ओर ध्यान आकर्षित करना, सतत कृषि और मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों की आय में मधुमक्खी पालन के योगदान को रेखांकित करना आदि शामिल है। हाल फिलहाल, यहां पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि पिछले वर्ष इस दिवस की थीम-प्रकृति से प्रेरित मधुमक्खियां, हम सभी का पोषण करती हैं रखी गई थी, जबकि इस वर्ष 2026 की थीम-लोगों और पृथ्वी के लिए मधुमक्खियों के साथ मिलकर कार्य करें निर्धारित की गई है। बहरहाल,यदि हम यहां पर इस दिवस के इतिहास की बात करें, तो इसकी शुरुआत का प्रस्ताव सर्वप्रथम यूरोपीय देश स्लोवेनिया ने रखा था। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2017 में 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस घोषित किया तथा पहली बार यह दिवस वर्ष 2018 में मनाया गया। 20 मई की तिथि इसलिए चुनी गई, क्योंकि इसी दिन आधुनिक मधुमक्खी पालन के अग्रदूत एंटोन जान्सा का जन्म हुआ था। मधुमक्खियों के महत्व की यदि हम बात करें तो ये नीले ग्रह (पृथ्वी) के पारिस्थितिक संतुलन की प्रमुख आधारशिला मानी जाती हैं। एक उपलब्ध जानकारी के अनुसार लगभग 75 प्रतिशत खाद्य फसलें किसी न किसी रूप में परागणकर्ताओं पर निर्भर हैं, जबकि दुनिया के लगभग 90 प्रतिशत जंगली पुष्पीय पौधों के प्रजनन में परागण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फल, सब्जियां, तिलहन, मेवे तथा अनेक औषधीय पौधों का उत्पादन मधुमक्खियों के कारण ही संभव हो पाता है। ये जैव-विविधता को बनाए रखने में सहायता करती हैं तथा कृषि उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने में भी सहायक होती हैं। यदि मधुमक्खियां न रहें, तो खाद्य-श्रृंखला और संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है। पाठकों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक मधुमक्खी अपने पूरे जीवन(जीवनकाल में) में लगभग एक चम्मच का बारहवां हिस्सा ही शहद बना पाती है और एक किलोग्राम शहद तैयार करने के लिए मधुमक्खियों को लाखों फूलों से बहुत मेहनत से रस एकत्र करना पड़ता है।इसके अलावा, मधुमक्खियां पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और सूर्य की दिशा के आधार पर अपना रास्ता पहचान सकती हैं। उनका वैगल डांस एक विशेष संचार प्रणाली है, जिसके माध्यम से वे अन्य मधुमक्खियों को भोजन की दिशा और दूरी तक की जानकारी देती हैं। शहद हजारों वर्षों तक भी खराब नहीं होता है; यहां तक कि मिस्र के पिरामिडों में मिला शहद भी खाने योग्य पाया गया था। मधुमक्खी दिखने में भले ही एक छोटा सा जीव/कीट है लेकिन आज मधुमक्खी पालन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और अतिरिक्त आय का महत्वपूर्ण स्रोत बनता जा रहा है।पृथ्वी पर लगातार बढ़ती आबादी, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और तीव्र विकास गतिविधियों के कारण ग्रीनहाउस गैसों का दबाव निरंतर बढ़ रहा है। कहना गलत नहीं होगा कि आज नीला ग्रह कही जाने वाली पृथ्वी पर मानवीय गतिविधियों के कारण जलवायु में व्यापक परिवर्तन हो रहे हैं। इन परिवर्तनों का प्रभाव तापमान, मौसम-चक्र, हिमखंडों, महासागरों और प्राकृतिक तंत्रों पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इसका असर मानव जीवन के साथ-साथ वनस्पतियों और कीट प्रजातियों पर भी पड़ रहा है, विशेष रूप से मधुमक्खियों पर। आज मधुमक्खियों की संख्या निरंतर घटती जा रही है और इसका खुलासा हाल ही में जर्मनी के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोधों में भी हुआ है। कुछ शोधों और अध्ययनों में यह अनुमान लगाया गया है कि 1970 के दशक के बाद से कीट बायोमास, विशेषकर मधुमक्खियों की संख्या, लगभग आधी रह गई है। जूलियस मैक्सिमिलियन्स यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक अध्ययन में जर्मनी के 179 क्षेत्रों में भूमि उपयोग और बढ़ते तापमान के संयुक्त प्रभावों का विश्लेषण किया गया। इस अध्ययन के निष्कर्ष रॉयल सोसाइटी ऑफ बायोलॉजी की पत्रिका बायोलॉजिकल साइंसेज में प्रकाशित हुए। अध्ययन में सामने आया कि मधुमक्खियां केवल दिन के उच्च तापमान से ही नहीं, बल्कि औसत से अधिक गर्म रातों से भी प्रभावित होती हैं। जानकारी के अनुसार रात के औसत तापमान में वृद्धि दिन के तापमान की तुलना में अधिक तेज़ी से हो रही है, जिससे कीटों पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है।इतना ही नहीं, आज मधुमक्खियों को खुले क्षेत्रों में आवास बनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, वे बढ़ते तापमान से निपटने में काफी सक्षम होती हैं, फिर भी कृषि भूमि, प्राकृतिक आवासों के विनाश, वायु प्रदूषण, खेती में अंधाधुंध कीटनाशकों और रसायनों के प्रयोग तथा खेती के बदलते तौर-तरीकों के कारण इनके अस्तित्व पर संकट गहराता जा रहा है।

क्या वैभव सूर्यवंशी इंटरनेशनल डेब्यू के लिए तैयार नहीं?

- IPL में शॉर्ट पिच से स्लोअर बॉल तक कई कमियां उजागर

नई दिल्ली। वैभव सूर्यवंशी का जोश हेजलवुड, जसप्रीत बुमराह, मिचेल स्टार्क और ट्रेंट बोल्ट के ऊपर सिक्सर की चर्चा सबने की। मगर वैभव का प्रफुल हिंगे के खिलाफ शॉर्ट पिच गेंद पर विकेट। उसके बाद रविवार को दिल्ली कैपिटल्स के माधव तिवारी की स्लोअर गेंद पर वैभव का विकेट फेंकना, इन बातों पर चर्चा नहीं हुई लेकिन क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने इन चीजों में वैभव की कमियों को बारीकी से पकड़ लिया। यही कारण है कि अभी 15 वर्षीय बल्लेबाजो को कड़ी मेहनत करनी है और शायद वह इंटरनेशनल

क्रिकेट के लिए तैयार नहीं हैं। वैभव सूर्यवंशी इन दिनों क्रिकेट जगत का हॉट टॉपिक हैं। हर कोई यही सवाल कर रहा है कि उनके टीम इंडिया में डेब्यू का सही समय क्या है। पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने तो यह तक कहा है कि उनकी उम्र कुछ भी हो लेकिन वैभव को टीम के टी20 फॉर्मेट में कम से कम जगह मिलनी चाहिए। इसके अलावा हरभजन सिंह लगातार वैभव को टीम इंडिया में लाने की मांग कर रहे हैं।

दिग्गजों की बंटी राय...

एक तरफ कुछ ऐसे दिग्गज हैं जिनका मानना है कि वैभव सूर्यवंशी इंटरेशनल डेब्यू के लिए तैयार हैं। वहीं एक पक्ष ऐसा भी है जिसका मानना है कि अभी वैभव के सामने कई चुनौतियां आना बाकी है, अभी वैभव हर वर्ग में मजबूत नहीं हुए हैं। वैभव से पहले भी कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो लंबे समय से खुद को साबित कर रहे हैं। एबी डिविलियर्स ने हाल ही में कहा था कि, अगर वैभव को टी20 का स्पेशलिस्ट बनकर ही रहना है तो वह जारी रख सकते हैं और लंबे समय तक अपना करियर आगे ले जा सकते हैं। लेकिन अगर बात वनडे और टेस्ट क्रिकेट की आती है तो वैभव सूर्यवंशी को आने वाले समय में और अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। मोहम्मद कैफ ने वैभव सूर्यवंशी की फील्डिंग क्षमताओं पर सवाल उठाए थे। उनका मानना था कि टीम इंडिया में खेलने के लिए आपकी फील्डिंग में चपलता जरूरी है। वैभव ने मौजूदा आईपीएल 2026 के 12 मैचों में एक भी कैच नहीं पकड़ा है। चेतेश्वर पुजारा का मानना है कि बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं हैं उनसे पहले भी यशस्वी जायसवाल जैसे अनुभवी और युवा खिलाड़ी हैं जो टीम इंडिया में जगह के हकदार हैं। वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल 2026 में प्रफुल हिंगे, मोहम्मद सिराज जैसे गेंदबाजों ने बॉडी लाइन शॉर्टपिच गेंदों पर टेस्ट किया है। वैभव की ताकत है कि वह बाहर की गेंद, पैर की गेंद और विकेट के सामने की गेंद सभी को बाउंड्री पार पहुंचाते हैं, लेकिन शॉर्ट पिच गेंदों के आगे वह फंस जाते हैं।

चेन्नई को हरा प्लेऑफ में पहुंची सनराइजर्स

इशान, क्लासेन और कमिंस चमके

नई दिल्ली। इशान किशन के 70 रन और पैट कमिंस के तीन विकेट की मदद से सनराइजर्स हैदराबाद ने सोमवार को चेन्नई सुपर किंग्स को पांच विकेट से हराकर इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में प्लेआफ में जगह पक्की कर ली। जीत के लिये 181 रन का लक्ष्य चेपक की धीमी विकेट पर आसान नहीं था, लेकिन इशान ने 47 गेंद की अपनी पारी में सात चौके और तीन छक्के लगाकर इसे आसान बना दिया। हेनरिक क्लासेन ने 26 गेंद में 47 रन बनाये और दोनों ने तीसरे विकेट के लिये 75 रन की साझेदारी करके हैदराबाद को 19 ओवर में पांच विकेट पर 181 रन तक पहुंचाया। सनराइजर्स के अब 16 अंक है और उसे एक मैच और खेलना है। चेन्नई सुपर किंग्स की हार के बाद गुजरात टाइटंस (16 अंक) भी प्लेआफ में पहुंच गई है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (18 अंक) पहले ही प्लेआफ में पहुंच चुकी है और अब बस एक स्थान के लिये मुकाबला है। चेन्नई के 13 मैचों में 12 अंक है और वह दौड़ से पूरी तरह बाहर नहीं हुई है।

क्लासेन को जीवनदान

अभिषेक शर्मा भी 21 गेंद में 26 रन ही बना सके। पावरप्ले में स्कोर एक विकेट पर 45 रन था। क्लासेन को नूर अहमद की गेंद पर 18 के स्कोर पर स्पेंसर जॉनसन ने जीवनदान दिया। इसके बाद क्लासेन और इशान ने मैच का नक्शा ही बदल दिया। दोनों ने चेन्नई के स्पिनरों अकील हुसैन और नूर अहमद को सहजता से खेला। इशान ने 37 गेंद में 50 रन पूरे किये। वहीं नूर की गेंद पर संजू सैमसन की कुशल स्टम्पिंग का शिकार होकर क्लासेन आउट हो गए।

चेन्नई सुपर किंग्स ने 180 रन बनाये– इशान को अंशुल कम्बोज ने आउट किया, लेकिन उस समय सनराइजर्स को जीत के लिये छह रन की ही जरूरत थी। इससे पहले कमिंस ने अनुशासित गेंदबाजी करते हुए 28 रन देकर तीन विकेट लिये, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने सात विकेट पर 180 रन बना लिये।

पीरियड्स एक सामान्य प्रक्रिया

एक जागरूकता कार्यक्रम में कहा इस पर बिना संकोच चर्चा होना चाहिएः स्मृति मंधाना

मुंबई। भारत में क्रिकेट और क्रिकेटरों की लोकप्रियता किसी भी खेल और खिलाड़ियों से ज्यादा है। यही वजह है कि क्रिकेटरों को सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हुए देखा जाता है। इसकी वजह उनकी कही बात का असर बड़े जनमानस पर पड़ना है। मुंबई में महिलाओं की पीरियड्स (मासिक धर्म) से जुड़ी समस्याओं से संबंधित एक जागरूकता कार्यक्रम में भारतीय महिला क्रिकेट की उपकप्तान स्मृति मंधाना ने हिस्सा लिया और इस विषय पर सामान्य रूप से चर्चा किए जाने की जरूरत पर बल दिया। मंधाना ने कहा, 'गांव में पीरियड्स के बारे में बातचीत दबी जुबान में होती है। इसे छुपाया जाता है, जबकि यह एक सामान्य प्रक्रिया है। इस पर बिना झिझक के चर्चा की जानी चाहिए। मैं अपनी तरफ से हर प्रयास करूंगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में इसे लेकर जागरूकता फैले और चीजें सामान्य हो।' भारतीय उपकप्तान ने संबंधित संस्था की प्रशंसा करते हुए कहा कि मुझे इस कार्यक्रम से जुड़कर अच्छा महसूस हो रहा है। यह काफी रोमांचक है। संस्था द्वारा गांव-गांव में पीरियड्स जागरूकता संबंधी कई अभियान चल रही हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि ये कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा और मेरी जरूरत जहां भी होगी मैं आउंगी। हम मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता के बारे में कार्य करते रहेंगे। हमारा लक्ष्य जीरो पीरियड को बढ़ावा देना है।

इस दौरान मंधाना उन स्कूली छात्राओं से मिलीं, जो क्रिकेट खेलती हैं। इस पर उन्होंने कहा, 'छोटे-छोटे बच्चों से मिलना और उनसे बातें करना काफी रोमांचक था। लंबे समय बाद स्कूल में आने का मौका मिला। मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ गए। '

छात्राओं को आप क्या संदेश देती हैं? इस पर भारतीय टीम की सलामी बल्लेबाज ने कहा, 'मैं उनसे कहती हूं कि क्रिकेट को गंभीरता से लें। इसमें बेहतर करियर बनाया जा सकता है। खेल में करियर बनाने के लिए कठिन मेहनत जरूरी है और उसका आनंद लेना भी जरूरी है। मैंने यही किया है। मैं हर किसी को सलाह दूंगी कि अपने जीवन में खेल को शामिल करें। फिटनेस के लिए यह बहुत जरूरी है। '

प्रीमियर लीग

खिताब के करीब पहुंचा आर्सेनल, बर्नले को 1-0 से हराया

लंदन। आर्सेनल एफसी सोमवार को बर्नले एफसी पर 1-0 की रोमांचक जीत के बाद 22 साल में अपने पहले प्रीमियर लीग खिताब के करीब पहुंच गया। आर्सेनल के लिए मैच में एकमात्र गोल काई हैवर्ट्ज ने किया। हाफटाइम से ठीक पहले बुकायो साका के कॉर्नर पर हैवर्ट्ज ने शानदार हेडर की मदद से गोल दागा। इसके बाद दोनों टीमों ने गोल करने के काफी प्रयास लिए, लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिल सकी। आर्सेनल एक मैच बाकी रहते टेबल में टॉप पर पांच पॉइंट की बढ़त बना चुका था। हालांकि, मैनचेस्टर सिटी एफसी को अभी भी दो मैच खेलने हैं, और अगर वे मंगलवार को एएफसी बॉर्नमाउथ को हरा देते हैं, तो वह खिताब की रेस में बने रहेंगे। वहीं, अगर इस मुकाबले में सिटी को हार का सामना करना पड़ता है, तो क्रिस्टल पैलेस एफसी के खिलाफ अपने आखिरी मैच से पहले आर्सेनल चैंपियन बन जाएगा।

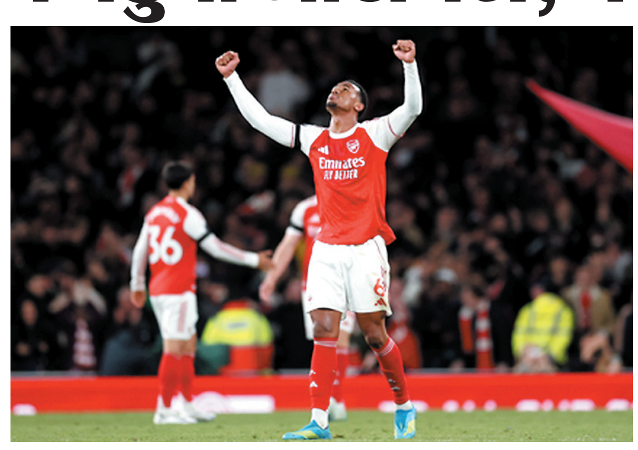

आर्सेनल ने नॉर्थ लंदन में जोश भरे माहौल के साथ मैच में एंट्री की। बर्नले के रेलिगेट होने और स्थायी मैनेजर के बिना होने के बावजूद, आर्सेनल को जीत के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। मेहमान टीम ने हैनिबल मेजब्री के साथ शुरुआत में दबाव बनाया, जबकि आर्सेनल को भारी उम्मीदों के बीच अपनी लय पाने में मुश्किल हुई। हालांकि, धीरे-धीरे आर्टेटा की टीम ने मैच को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। एबेरेची एजे ने गोलकीपर मैक्स वीस को परखा। लुकास पाइरेस के चैलेंज पर साका के गिरने के बाद आर्सेनल ने पेनल्टी के लिए भी नाकाम अपील की। आर्सेनल को फिर से एक तयशुदा मौके (सेट-पीस) से सफलता मिली। इस पूरे सीजन में टीम कॉर्नर और फ्री-किक जैसे मौकों पर बहुत अच्छा खेली है। साका ने शानदार क्रॉस दिया, जिसे हैवर्ट्ज ने शानदार हेडर से इस सीजन में कॉर्नर से आर्सेनल का 18वां लीग गोल किया। एमिरेट्स में टेंशन थोड़ी देर के लिए कम हुई, लेकिन हाफ टाइम के बाद आर्सेनल मैच पर पूरी पकड़ नहीं बना सका। एजे का शॉट क्रॉसबार से टकराकर वापस आ गया। वहीं, हैवर्ट्ज के एक कड़े टैकल को वीएआर ने रेड कार्ड के लिए रिव्यू किया, लेकिन आखिर में उन्हें सिर्फ येलो कार्ड दिया गया।

व्यापार

सरकार की जेब पर बढ़ेगा 70,000 करोड़ रु. का अतिरिक्त बोझ

नई दिल्ली, एजेंसी। पश्चिम एशिया में जारी तनाव का असर अब भारत के उर्वरक सब्सिडी बिल पर भी पड़ता दिख रहा है। सरकार का उर्वरक सब्सिडी खर्च वित्त वर्ष 2026-27 में अतिरिक्त करीब 70,000 करोड़ रुपये बढ़कर 2.41 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। इसकी मुख्य वजह यूरिया और अन्य उर्वरकों के आयात खर्च में तेज बढ़ोतरी मानी जा रही है। उर्वरक विभाग की अतिरिक्त सचिव अपर्णा एस. शर्मा ने सोमवार को पश्चिम एशिया से जुड़े अंतर-मंत्रालयी ब्रीफिंग के दौरान कहा कि सब्सिडी बिल बढ़ेगा, लेकिन यह कितने प्रतिशत बढ़ेगा, अभी कहना मुश्किल है। जब उनसे पूछा गया कि क्या यह बढ़ोतरी 70,000 करोड़ रुपये तक हो सकती है, तो उन्होंने कहा, 'हो सकता है।' बता दें कि बजट में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उर्वरक सब्सिडी के मद में 1.71 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। अतिरिक्त सचिव शर्मा ने स्पष्ट किया कि बढ़ती लागत के दबाव के बावजूद साल 2026 के आगामी खरीफ सीजन के लिए देश में उर्वरकों का पर्याप्त स्टॉक है।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में 390 लाख टन की कुल आवश्यकता का 51 प्रतिशत से अधिक स्टॉक पहले से ही मौजूद है। बाकी के अंतर को अलग-अलग देशों से आयात के जरिए पूरा किया जा रहा है। वर्तमान में देश में 200.9 लाख टन उर्वरक का स्टॉक उपलब्ध है। देश में घरेलू उत्पादन लगभग 80,000 टन प्रतिदिन की दर से चल रहा है। पश्चिम एशिया संकट की शुरुआत से अब तक कुल उत्पादन 86.2 लाख टन रहा है, जो पिछले साल की इसी अवधि के 93 लाख टन से थोड़ा कम है। उर्वरक उत्पादन में मामूली कमी आई है, जिसे हम आने वाले महीनों में पूरा करने की उम्मीद करते हैं। यूरिया प्लांटों के लिए पर्याप्त गैस आपूर्ति उपलब्ध है। सुरक्षित रखने के लिए भारत ने होर्मुज जलडमरूमध्य से हटकर अपने आयात मार्गों में सक्रिय रूप से विविधता ला दी है। इसके तहत अब तक 22 लाख टन से अधिक उर्वरक भारतीय तटों पर सुरक्षित पहुंच चुका है।

कंसोर्टियम आधारित खरीद प्रणाली के माध्यम से भारत ने अमोनियम सल्फेट, फॉस्फेट और अन्य कच्चे माल के अलावा, लगभग 13.5 लाख टन डाई-अमोनियम फॉस्फेट और 7 लाख टन कॉम्प्लेक्स सुरक्षित कर लिया है।

ईरान युद्ध के बीच मंदिरों का सोना बेचने जा रही सरकार? वित्त मंत्रालय ने बताई सच्चाई

नई दिल्ली, एजेंसी। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय घरों और मंदिरों में करीब 50,000 टन सोना है जिसकी कीमत करीब 10,000 अरब डॉलर है। इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स में दावा किया गया है कि सरकार मंदिरों में रखे गए सोने के बदले उन्हें गोल्ड बॉन्ड जारी करने की योजना बना रही है। साथ ही यह भी दावा किया जा रहा है कि मंदिरों में रखे सोने के मोनेटाइजेशन से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। लेकिन सरकार ने इन दावों को फर्जी और गुमराह करने वाला बताया है।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा कि इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है कि सरकार मंदिर ट्रस्टों या धार्मिक संस्थानों के पास मौजूद सोने के लिए मोनेटाइजेशन स्कीम ला रही है। इनमें कोई सच्चाई नहीं हैं। ये निराधार और गुमराह करने वाली हैं। सरकार ने साथ ही साफ किया है कि मंदिरों के स्तंभों, दरवाजों या किसी अन्य ढांचे पर मढ़े गए सोने को स्ट्रैटजिक गोल्ड रिजर्व घोषित करने के दावे भी झूठे हैं और इनका कोई आधार नहीं है। बयान में लोगों से अनुरोध किया गया है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें। इस तरह की अपुष्ट खबरों से लोगों में भ्रम पैदा होता है। सरकार ने सभी लोगों से अनुरोध किया है कि वे केवल आधिकारिक बयानों पर भरोसा करें। सरकार की तरफ से लिए जाने वाले किसी भी फैसले या स्कीम की जानकारी आधिकारिक प्रेस रिलीज, सरकारी वेबसाइट और वेरिफाइड पब्लिक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स पर साझा किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान युद्ध के मद्देनजर देशवासियों से पेट्रोल-डीजल और खाने के तेल की खपत कम करने, एक साल तक सोना नहीं खरीदने, रासायनिक खाद का प्रयोग कम करने और विदेश यात्रा से परहेज करने की अपील की थी। इससे विदेशी मुद्रा बचेगी और चालू खाते का घाटा कम होगा। इससे रुपये पर भी दबाव कम होगा। इस साल रुपये की कीमत में भारी गिरावट आई है और यह एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी है।

बच्चे बीमार पड़े तो आया बिजनेस का आईडिया, सरकारी नौकरी छोड़ी

6 महीने तक नाकाम रहे, आज करोड़ों की कमाई

नई दिल्ली, एजेंसी। आज भारतीय घरों में वॉटर प्यूरीफायर होना एक आम बात है, लेकिन 1990 के दशक के आखिरी सालों में ऐसा बिल्कुल नहीं था। उस दौर में भारत में पानी साफ करने का कोई संगठित बाजार नहीं था। बाजार में गिने-चुने अल्ट्रावायलेट प्यूरीफायर थे, जिन पर लोग ज्यादा भरोसा नहीं करते थे। साफ पानी सबकी जरूरत तो था, लेकिन यह कोई बड़ी कमर्शियल कैटेगरी नहीं बनी थी। इसी दौर में कानपुर से पढ़े मैकेनिकल इंजीनियर डॉ. महेश गुप्ता के सामने एक ऐसा संकट आया जिसने भारत में वाटर प्यूरीफिकेशन इंडस्ट्री की तकदीर बदल दी। डॉ. महेश गुप्ता आज केंट आरओ सिस्टम्स के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं।

यह कहानी किसी बड़े बिजनेस प्लान से नहीं, बल्कि एक घरेलू समस्या से शुरू होती है। डॉ. महेश गुप्ता के बच्चे दूषित पानी पीने की वजह से पीलिया (जॉन्डिस) के शिकार हो गए। एक इंजीनियर होने के नाते डॉ. गुप्ता ने इसके मूल कारण पर रिसर्च शुरू की। वे बताते हैं कि बाजार में मौजूद ङ्क प्यूरीफायर पानी में घुले हानिकारक कणों को नहीं हटा पा रहे थे।

तब उन्हें समझ आया कि इसका एकमात्र इलाज रिवर्स ऑस्मोसिस तकनीक है। भारत

में तब यह तकनीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने अमेरिका से मेम्ब्रेन और पंप जैसे पार्ट्स मंगवाए और घर पर ही पहला प्यूरीफायर असेंबल किया। जब वह सिस्टम कामयाब रहा, तो डॉ. गुप्ता को अहसास हुआ कि जो तकनीक उनके परिवार के काम आई, उसकी जरूरत पूरे देश को है। यहीं से जन्म हुआ।

नौकरी छोड़कर लिया रिस्क

आईआईटी कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद डॉ. महेश गुप्ता इंडियन ऑयल जैसी प्रतिष्ठित सरकारी कंपनी में एक क्लास-वन ऑफिसर की नौकरी कर रहे थे। लेकिन जब दूषित पानी के कारण उनके बेटे की तबीयत खराब हुई, तो इस घरेलू संकट ने उन्हें नौकरी छोड़कर कुछ नया करने की प्रेरणा दी। उन्होंने महज 20,000 रुपये की मामूली पूंजी के साथ रिस्क लिया और बिजनेस की शुरुआत की। 2 बेटियों का जिम्मा, नौकरी, खाना बनाते हुए की तैयारी, छठी बार में अफसर बनीं बरेली की बहू हुमा डॉ. गुप्ता ने अमेरिका से एक खास मेम्ब्रेन और पंप मंगवाकर शुरुआती वॉटर प्यूरीफायर बनाने पर काम शुरू किया। हालांकि, यह सफर इतना आसान नहीं था। डॉ. गुप्ता ने लगातार 6 महीने तक दिन-रात मेहनत की और हर संभव तकनीक आजमाई, लेकिन वे पानी की अशुद्धियों को पूरी तरह अलग करने में नाकाम रहे। इस शुरुआती असफलता के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और 6 महीने के कड़े संघर्ष और तकनीकी प्रयोगों के बाद आखिरकार उन्होंने उस सटीक फॉर्मूले को खोज निकाला।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सैयद ज़की हैदर के लिए इरानीयन आर्ट प्रिंटर्स 1534 कासिमजान स्ट्रीट दरियागंज नई दिल्ली 11006 से मुद्रित कराकर, 2684 गली काले खां कूचा चलान दरियागंज नई दिल्ली 02 से प्रकाशित किया।
संपादक : सैयद ज़की हैदर- हैड ऑफिस :- एफ19/4 सेकेंड फ्लोर नफीश रोड जामिया नगर दिल्ली- 110025., सम्पर्क सूत्र :- 9911371802, 9810383593
जितेन्द्र कुमार बिस्वाल ब्यूरो चीफ उड़ीसा/ गोविंद कनोडिया/ पटना/ सैय्यद यूसुफ अली नक़वी-पॉलिटिकल एडिटर। ई-मेलः- (LOKTANTRAKISHAAN@GMAIL.COM

किसी भी प्रकार के विवाद हेतु निपटारे के लिए केवल दिल्ली न्यायालय ही मान्य होगी।
नोट- किसी भी समाचार/आलेख पर दावा प्रति दावा/आपत्ति समाचार प्रकाशन के 15 दिनों के अन्तराल तक ही मान्य होगा। समाचार पत्र में प्रकाशित आलेख से संपादक/प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

क्षेत्रीय कार्यालय अनवार मंजिल नया टोला गंज नंबर 01 बेतिया/ बिहार/ पिन नंबर 84 5438/>> संवाददाता, सना खान/(डॉ. अमानुल हक) स्थानीय संपादक/बिहार)